● वर्ष-5

● अंक-282

रायपुर, रविवार
12 जुलाई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> वन मंत्री ने हरी झंडी...

न्यूजीलैंड भारत में करेगा 20 अरब डॉलर का निवेश

पीएम मोदी बोले- हिंदुस्तान वैश्विक विकास का लॉन्च पैड

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि वैश्विक विकास के लिए एक लॉन्च पैड है। भारत-न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशक समुदाय के समक्ष बहुत ही जोरदार तरीके से पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को वैश्विक कंपनियों के लिए अनूठा अवसर बताया।

अवसरों के नए द्वार खोलेगा

पीएम ने भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बाजार, निवेश, सेवाओं, तकनीक और प्रतिभाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा। पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे थे। दो दिनों के कार्यक्रम के बाद वह भारत के लिए

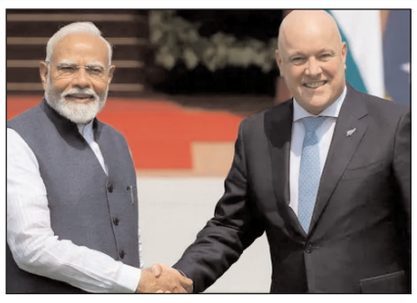

शनिवार दोपहर को रवाना हो गये।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग प्वाइंट पर हैं। संबंधों को रणनीतिक संबंध का दर्जा देना सिर्फ एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारे साझा भविष्य का नया संकल्प है।

न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का कमिटमेंट दिया गया है, जो न सिर्फ निवेश बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का संकेत है। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बढ़ती मध्यम वर्ग, व्यापक डिजिटल अपनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारतीय विकास को अनूठी बनाती है। प्रधानमंत्री ने कारोबारी दुनिया की हस्तियों को भारत के मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बनने का न्योता दिया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण से लेकर टेक्सटाइल तक 14 सेक्टर्स में करीब 20 अरब डॉलर का सपोर्ट दिया जा रहा है। एविएशन सेक्टर में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। एयरपोर्ट्स, रीजनल कनेक्टिविटी और एयर कार्गो में तेज वृद्धि हो रही है।न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कार्गो कॉरिडोर, फ्लाइट कनेक्टिविटी और संयुक्त टूरिज्म पैकेज बना सकते हैं।पीएम मोदी ने कहा कि कीवी, सेब, शहद और सीफूड जैसे नष्ट होने वाले सामान के लिए बेहतर कार्गो सोल्यूशन विकसित किए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में न्यूजीलैंड की हॉर्टिकल्चर, दुग्ध विज्ञान विशेषज्ञता व भारतीय बाजार के लिए पूरा खेत से बाजार तक का वैल्यू चेन व वैश्विक निर्यात प्लेटफार्म बनाने का सुझाव भी पीएम मोदी ने दिए। फिनटेक में भारत ग्लोबल लीडर है, जहां दुनिया की 50 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। ग्रीन बांड्स और ब्लेंडेड फाइनेंस में भी सहयोग बढ़ाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में 8,000 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है जहां वाहन, जल व कचड़ा प्रबंधन में सहयोग के अवसर हैं।न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत में हुए आर्थिक बदलाव को करीब से अनुभव करने की बात कही और दोनों देशों के कारोबारियों से आग्रह किया कि वे व्यापार के नये अवसर खोलने के लिए तैयार रहें।

भारतीय समुदाय को किया संबोधित

नमस्ते, की ओरा न्यूजीलैंड के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करने वाले पीएम मोदी ने कहा, हम भारत के लोग सुनते आए थे, 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही ये मेरा पहला दौरा है। लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे न्यूजीलैंड आने का मौका मिला था।

प्रधानमंत्री ने वर्षों पुरानी यात्रा से जुड़ी यादें ताजा करते हुए कहा, उस समय किसी ने मुझे गिफ्ट में तीन चीजें दी थीं जो मैं वापस भारत लेकर गया था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। उसमें से एक चीज मैं यहां इस कार्यक्रम में भी लाया हूं। ये मफलर 25-30 साल पहले न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था।

दुनिया में तीसरी सर्वश्रेष्ठ है भारतीय वायुसेना

चीन को पछाड़ा; पहले और दूसरे स्थान पर कौन?

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं की ताजा रैंकिंग में लगातार अपनी तीसरी स्थिति बरकरार रखी है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना लगातार पांचवें आकलन में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स से आगे रही है।

डब्ल्यूडीएमएए की 2026 रैंकिंग के अनुसार, भारतीय वायुसेना से ऊपर केवल अमेरिका और रूस की वायु सेनाएं हैं। यह रैंकिंग दुनिया की प्रमुख सैन्य वायु शक्तियों में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। डब्ल्यूडीएमएए हर साल 103 देशों की 129 वायु सेनाओं का आकलन करता है। इसमें दुनिया भर के 48,000 से अधिक सैन्य विमानों का विश्लेषण किया जाता है। रैंकिंग संगठन की %ट्रू वैल्यू रेटिंग% (टीवीआर) प्रणाली पर आधारित होती है। इसमें केवल विमानों की संख्या नहीं, बल्कि बेड़े की संरचना, तकनीकी क्षमता, लॉजिस्टिक समर्थन, आधुनिकीकरण और कुल परिचालन क्षमता को भी आधार बनाया जाता है।

ताजा रैंकिंग में भारतीय वायुसेना एक बार फिर चीन की वायुसेना से आगे रही है। रिपोर्ट के अनुसार, यह छठा मौका है, जब वैश्विक रैंकिंग में भारतीय वायुसेना अमेरिका और रूस के बाद तीसरे स्थान पर रही है। डब्ल्यूडीएमएए की रैंकिंग केवल लड़ाकू विमानों की संख्या पर आधारित नहीं होती। इसमें एयर फोर्स के पूरे बेड़े की विविधता और उसकी परिचालन क्षमता को अधिक महत्व दिया जाता है।हवाई ईंधन भरने वाले विमान, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, परिवहन विमान, प्रशिक्षण विमान, खुफिया जानकारी जुटाने वाले प्लेटफॉर्म और क्लोज एयर सपोर्ट विमान जैसे विशेष प्लेटफॉर्म भी रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पर्यटकों की नाव वियतनाम में डूबी, 15 भारतीय लोगों की मौत

वियतनाम। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को ले जा रही नाव डूबने की खबर है। हनोई में भारतीय दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कुछ घंटे पहले वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास एक दुखद घटना में कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई। स्थानीय अधिकारियों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। हादसे के कारण और नाव पर सवार लोगों के सटीक विवरण जुटाए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है।समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सभी भारतीय हैं। स्थानीय समय के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब एक बजे ओशन पीयर आइलैंड कंपनी की ओर से संचालित स्पीडबोट हॉन मे रट नाम की जगह से पर्यटकों को लेकर एन थॉई पोर्टकी ओर जा रही थी। फु क्वोक हवाई अड्डे से लगभग 25 किलोमीटर दूर होन मे रट एन्वाई नाम की जगह से करीब 400 मीटर दूर नाव पलट गई।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में बस्तर गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गोंचा महापर्व-2026 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए महापर्व के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ को पारंपरिक रूप से दी जाने वाली सलामी तुपकी चलाकर महापर्व की सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान किया। (**विस्तृत समाचार पेज-8 पर**)

सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नीता अंबानी को पहला स्थान

नई दिल्ली। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता एम अंबानी को फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान मिला है। उनके नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन भारत भर में 10 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ा है, जिसमें 2 करोड़ 90 लाख बच्चे भी शामिल हैं। यह सम्मान उनके दूरदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नीता अंबानी की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि यह सम्मान उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक

है। यह संस्था-निर्माण और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। उनका मानना है कि सच्ची सफलता इस बात से मापी जाती है कि हम कितने लोगों का जीवन बदलने में योगदान देते हैं।

3 जुलाई को नीता अंबानी को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (एएपीआई) द्वारा प्रतिष्ठित एएपीआई मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह समारोह फ्लोरिडा के टाम्पा में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल, संस्कृति और सामुदायिक विकास में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है।मानवीय प्रयासों की आगे की मान्यता के रूप में, टाम्पा की महापौर जेन कैस्टर ने नीता अंबानी को %की टू द सिटी ऑफ टाम्पा% प्रदान की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

प्रमुख समाचार

आंध्रप्रदेश बन रहा देश का डिफेंस पावरहाउस : रक्षा मंत्री

अमरावती। शनिवार को विशाखापत्तनम में स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि को कमीशन करते हुए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश को देश के रक्षा ढांचे के लिए एक अहम नया केंद्र बताया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के एडवांस्ड प्रोजेक्ट 17 ए नीलगिरि-क्लास युद्धपोत

सीरीज़ का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पूर्वी तट पर आयोजित इस खास कमीशनिंग समारोह में बोलते हुए, राजनाथ सिंह ने कई तरह के युद्ध क्षेत्रों में राज्य की रणनीतिक भूमिका के बारे में बताया। मंत्री ने कहा ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश भारत के डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए पावरहाउस के तौर पर उभर रहा है। यह हवा, पानी, ज़मीन और बिना पायलट वाले सिस्टम - हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। पुट्टापर्थी में, हमने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी। अनाकापल्ली ज़िले में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी की आधारशिला भी रखी गई।

कांग्रेस ने भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को किया याद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के बीच कांग्रेस ने शनिवार को दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया है। पार्टी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान न्यूजीलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री

डेविड लैंग ने भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को एक नई दिशा देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा उन्हें एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की याद दिलाती है, जिन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम योगदान दिया था। जयराम रमेश ने बताया कि डेविड लैंग वर्ष 1984 से 1989 तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। अक्टूबर 1984 में पदभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की ही थी।

दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी

भोपाल। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं देना पार्टी का फैसला है और वह उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो मुझे दिखाये गए। पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल (केरोसिन तेल) डालते हुए लोग नजर आए।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ऐसा कोई भी काम न करें। मिश्रा ने कहा कि पार्टी के भीतर अपनी बात रखने का एक तय तरीका होता है और विरोध भी उसी मर्यादा में किया जाना चाहिए। दतिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने करीब 11-12 घंटे तक नेशनल हाईवे-44 जाम रखा। प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान दतिया के एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वानखेड़े ने साफ कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया।

पंजाब भाजपा ने आप पर लगाए चुनाव में धांधली के आरोप

चंडीगढ़। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर मोरिंडा में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में धांधली और हेरफेर करने का आरोप लगाया। शनिवार को उन्होंने गवर्नर गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपकर दखल देने की मांग की। गवर्नर से मिलने के बाद ढिल्लों ने कहा कि चुनावों में अभूतपूर्व अनियमितताएं हुईं और उन्हें राजभवन से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ढिल्लों ने कहा कि मुद्दा यह है कि पंजाब सरकार ने हाल के नगर निकाय चुनावों में इतनी बड़े पैमाने पर धांधली की है, जो किसी भी भारतीय राज्य के इतिहास में, और निश्चित रूप से पिछले 70 वर्षों में पंजाब में अभूतपूर्व है। जिन जगहों पर हमारा बहुमत था, वहां उन्होंने अपने सदस्यों को अंदर भेजा, दरवाजे बंद कर दिए और अपने ही उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया।

बंगाल में यूसीसी पर बड़ा दांव जस्टिस रंजना देसाई कमेटी बनी

कोलकाता। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।

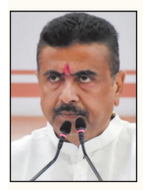

इससे राज्य में भाजपा का चुनावी वादा कानून बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक अगस्त में विधानसभा सत्र में यह बिल पेश किए जाने की संभावना है। समिति के आठ अन्य सदस्य मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय हैं; दुष्यन्त नरियाला, आईएएस और रेजिडेंट कमिश्नर; शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी; संघमित्रा घोष, प्रधान सचिव, गृह विभाग; बंगबासी कॉलेज की सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रत्ना भट्टाचार्य; गोपाल चंद्र मिश्रा, गौर बंगा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति; उस्मान गनी मलिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील; और सम्भाग के पूर्व कार्यकारी निदेशक निर्मल्या भट्टाचार्य। न्यायिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले, राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में समिति के अध्यक्ष जस्टिस देसाई के साथ बैठक की।

उत्तर भारत से क्यों साफ होती जा रही है कांग्रेस?

सचिन शर्मा

4 मई 2026 को असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव नतीजे आए। कांग्रेस का दक्षिण भारत में प्रदर्शन उत्तर भारत के मुकाबले फिलहाल बेहतर है। उसने केरल में सरकार बना ली। तमिलनाडु में टीवीके के सी।जोसेफ विजय के साथ सरकार में शामिल हो गई। कर्नाटक और तेलंगाना में वो पहले से ही सरकार में है। लेकिन उस उत्तर भारत और उत्तरपूर्वी राज्यों का क्या जहां एक समय कांग्रेस का एकछत्र शासन हुआ करता था। आज वो वहां हाशिए पर क्यों है। इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में कांग्रेस सिर्फ एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में पूर्ण सत्ता में है। जम्मू-कश्मीर में वो नेशनल कांफ्रेंस के साथ गंठबंधन की सरकार में है। उस सरकार में भी नेशनल कांफ्रेस का हाथ ऊंचा है। यही हाल झारखंड में है। जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की सरकार में है लेकिन वहां से उन दोनों ही दलों के बीच खटास की खबरें आती रहती हैं। उत्तर भारत के इन तीन राज्यों को छोड़े दें तो कांग्रेस कहीं नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो 141 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ऐसी गति को प्राप्त हो गई। यह भी तब जब वो ठीक 12 साल पहले तक केन्द्र सरकार में थी और वो भी पूरे एक दशक तक। जबकि भाजपा और एनडीए का शासन इस समय देश के 21 राज्यों में है। 14 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं।

उत्तर भारत में कांग्रेस के पतन और भाजपा के उभार के पीछे कई वजह हैं लेकिन मुख्य वजह दोनों पार्टियों की विचारधारा है। जहां भाजपा हिन्दुत्व की राजनीति करती है वहीं कांग्रेस अपने सेक्युलर सिद्धांत पर अडिग है लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के लिए जो मुस्लिम तुष्टिकरण वाला नेरेटिव चलाया उसका वो तार्किक रूप से जवाब नहीं दे पाई। हालिया उदाहरण असम के चुनावों का है। वहां कांग्रेस से ही भाजपा में आए हिमंता बिस्वा शर्मा हिन्दुत्व की आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। 126 सीटों वाली असम विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो भाजपा ने उसमें से 82 जबकि एनडीए ने कुल 102 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 19 सीटें मिलीं। इनमें से 18 मुस्लिम उम्मीदवार विजेता बनकर आए। भाजपा को बस यहीं मौका मिल गया। उसने इस बात का खूब प्रचार किया कि अब हिन्दुओं का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है और

कांग्रेस अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। जीत के बाद मुख्यमंत्री हिंमता ने मंच से अपनी स्पीच में भी कहा कि देखो कांग्रेस की असम में क्या हालत हो गई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने 207 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस ने सिर्फ दो। कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवारों के नाम मोहताब शेख (फरक्का विस) और जुल्फिकार अली (रानीगंज विस) हैं। यह नरेटिव सिर्फ असम या बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में भाजपा ने मजबूती से बनाने की कोशिश की है कि कांग्रेस अब धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धर्म विशेष की पार्टी बनकर रह गई है।

भारतीय राजनीति में कांग्रेस की राजनीति का ग्राफ उसी समय से नीचे गिरना शुरू हुआ जहां से भाजपा का ग्राफ उठना शुरू हुआ। 1989 के बाद से कांग्रेस आज तक कभी केन्द्र में पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई। पूर्ण बहुमत वाले आखिरी कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जबकि 1990 के बाद से भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है। भाजपा ने पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कनार्टक, गोवा और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाईं। इसके बाद 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की केन्द्र सरकार बनाई। इस हिसाब से देखें तो पिछले 36 साल भाजपा के लिए लगातार उत्थान के रहे हैं जबकि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। कांग्रेस को भाजपा यूं तो वंशवाद की राजनीति का प्रेरक बताती है लेकिन यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के शासन में हुए भ्रष्टाचार और तमाम घोटालों को भाजपा ने खूब उछाला भी और भुनाया भी। 2 जी स्प्रेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कामनवैल्थ घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड और आदर्श हाउसिंग घोटाला आदि 2014 के संसदीय चुनावों में मुख्य मुद्दा बने। कांग्रेस की आपसी कलह, उसका कमजोर होता संगठन और राज्य संगठनों में कुछ क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा उसको कमजोर बनाने वाला रहा। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभार ने भी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक हथिया कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया। सपा, बसपा, राजद और तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने कांग्रेस को 1990 के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस सबके बावजूद कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान राम के मुद्दे से हुआ है।

1984 से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही भाजपा देश में मजबूत होती गई। कांग्रेस इस मुद्दे से हमेशा असहज रही है। 1992 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार, मध्यप्रदेश की सुंदरलाल पटवा सरकार, राजस्थान की भैरों सिंह शेखावत सरकार और हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार सरकार को एकसाथ बर्खास्त कर दिया था। चारों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

अपोलो अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का छापा, एयर एंबुलेंस में लापरवाही मामले की जांच कर रही टीम

बिलासपुर। शहर के अपोलो अस्पताल की लापरवाही से पूर्व मेयर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला की मौत के बाद अब एयर एम्बुलेंस में लापरवाही के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की आंदोलन की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आया और अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शहर के अपोलो अस्पताल में पिछले दो दिनों से चल रहे विवाद के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर और बिलासपुर से पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीम अस्पताल में व्यापक जांच कर रही है।जांच टीम अस्पताल में मरीजों के इलाज से जुड़े दस्तावेज, भर्ती और उपचार की प्रक्रिया, चिकित्सा रिकॉर्ड के साथ-साथ अस्पताल के आय-व्यय का भी बारीकी से परीक्षण कर रही है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के दस्तावेजों का मिलान कर आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है।
गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से अपोलो अस्पताल लगातार विवादों में बना हुआ है। मरीजों के उपचार और एंबुलेंस व्यवस्था में कथित लापरवाही के आरोप सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर, कांग्रेसी नेताओं ने भी अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपोलो अस्पताल में भर्ती एक गंभीर मरीज को हैदराबाद रेफर करने की प्रक्रिया के दौरान अस्पताल प्रबंधन पर कथित लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मरीज के परिजनों का दावा है कि समय पर समुचित चिकित्सा समन्वय नहीं होने के कारण एयर एंबुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद मरीज को उसी दिन हैदराबाद नहीं भेजा जा सका। इससे मरीज की हालत और गंभीर हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत राजकुमार अग्रवाल लगभग 12 दिन पहले दोस्तों के साथ कोलकाता घूमने गए थे।

चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला पैर आरपीएफ जवान ने बचाई जान

राजनांदगांव। मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर चेतन दिलीपराव जिचकार के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव के स्टाफ ने अपनी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री का जीवन बचाकर सराहनीय कार्य किया।

8 जुलाई को राजनांदगांव स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था।

इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगा। प्लेटफॉर्म ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक राजेंद्र रायकवार ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए यात्री को सुरक्षित खींच लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

पूछताछ में यात्री ने अपना नाम बृजेश सकुनिया (52 वर्ष), पिता महीबीर प्रसाद सकुनिया, निवासी हनुमान मंदिर पारा, झारसुगुड़ा बताया।

नक्सलमुक्त बस्तर के 100 दिन पूरे : जानिए कितना बदला अबूझमाड़ और कोहकामेटा का रक्तरंजित इतिहास

नारायणपुर। माओवाद के खूनी पैर अब बस्तर से उखड़ चुके हैं। जिस बस्तर से कभी बारूद की गंध आती थी और बमों के धमाके सुनाई पड़ते थे, आज उस बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है। बस्तर विकास के रास्ते पर चलने नहीं बल्कि दौड़ने लगा है। इस बदलाव की कहानी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और जवानों की हिम्मत से लिखी गई है।

अबूझमाड़ जिसे कभी माओवादियों की राजधानी भी कहा जाता था, आज वहां की सड़कों पर मुसाफिर बसें सरपट दौड़ रही हैं। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही बुनियादी सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा। घरों तक नल-जल योजना, गांव तक पीडीएस का राशन और स्कूल से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। 31 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था। नक्सलवाद के खात्मे के 100 दिन अब पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में क्या कुछ बदलाव नारायणपुर में आया इसको लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और विकास कार्यों को लेकर कई दावे भी किए। अबूझमाड़ के कोहकामेटा पहुंचे वन मंत्री और नारायणपुर के विधायक केदार कश्यप ने कहा, तेजी से विकसित होने वाले जिलों में जल्द नारायणपुर जिले का नाम शुमार किया जाएगा। ये दावा मंत्री केदार कश्यप ने अबूझमाड़ के कोहकामेटा हाई लेवल ब्रिज और विकास कार्यों को लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होन के बाद जो बदलाव यहां दिखाई पड़ना चाहिए था वो नजर आने लगा है। मंत्री ने कहा कि शासन की योजनाएं जनता तक पहुंचने लगी हैं। सरेंडर नक्सलियों को पुनर्वासित किया जा रहा है। केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलगढ़ अब विकासगढ़ की राह पर चल पड़ा है। करीब 4 दशकों तक नक्सलवाद और पिछड़ेपन का दंश झेलने वाला अबूझमाड़ आज विकास की नई राह पर बढ़ चला है। ये बदलाव विकास से और हिंसा के खत्म होने से आया है। विकास की राह में पिछड़े इलाकों को आगे लेकर आना हमारा लक्ष्य है दरअसल, अबूझमाड़ कभी वो इलाका हुआ करता था, जहां माओवादियों की समानांतर सरकार चला करती थी। माओवादी खुलेआम यहां बंदूक लेकर घूमा करते थे। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का यहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जिन जवानों से कभी ग्रामीण भय खाते थे उन जवानों को अब अपना ग्रामीण रक्षक मानने लगे हैं। जनता और सरकार के बीच की दूरी विश्वास का पुल बन जाने से खत्म हो चुकी है। कोहकामेटा में निर्मित हाई लेवल ब्रिज इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। वर्षों तक पुल के अभाव में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ता था। नक्सल प्रभावित परिस्थितियों के बीच जिला प्रशासन और पुलिस ने कभी यहां लोहे का अस्थायी पुल बनाया था, जिसे उस समय क्षेत्र की लाइफ लाइन माना गया।

दो दिनों में तीन चीतलों की मौत

बलौदाबाजार। बारनवापारा अभयारण्य में दो दिनों में तीन चीतलों की मौत हुई है। इन मौतों को लेकर मीडिया ने कई सवाल खड़े किए थे,जिनका खंडन वन विभाग ने किया है। वन विभाग के मुताबिक तीन मौतों की जांच की गई है।प्रथम दृष्टया दो नर चीतलों की मौत आपसी संघर्ष के दौरान हुई है,जबकि तीसरे चीतल का शिकार तेंदुआ ने किया है। बारनवापारा अभ्यारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें हिरणों की मौत को संदेहास्पद बताया गया था। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वन क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बारनवापारा अभ्यारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर के अनुसार 7 जुलाई 2026 को बारनवापारा अभ्यारण्य के पकरीद बीट अंतर्गत रामपुर चारागाह क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 127 में गश्त के दौरान दो नर चीतल मृत अवस्था में मिले थे। दोनों शवों का शासकीय शल्य पशु चिकित्सालय कसडोल में पोस्टमार्टम कराया गया। प्राथमिक जांच में दोनों चीतलों के गले में चोट के निशान मिले। इसके अगले दिन 8 जुलाई को उसी क्षेत्र के चारागाह इलाके में एक और चीतल मृत अवस्था में मिला।वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो मृत चीतल के गले पर हिंसक वन्यप्राणी के हमले के निशान मिले। बारनवापारा अभयारण्य अधीक्षक कृषाणु चंद्राकर के अनुसार मृत चीतल के सभी अंग, सींग और खाल सुरक्षित मिले हैं।घटनास्थल पर किसी भी तरह की शिकार से जुड़ी मानव गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं।घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में ट्रैप कैमरा लगाया था। विभाग के अनुसार कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि तीसरे चीतल का शिकार तेंदुआ ने किया है।

कृषाणु चंद्राकर ने बताया कि वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास में अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं की जाती है।सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

एक तरफ प्रवेशोत्सव दूसरी तरफ बदहाल तस्वीर

धमतरी में आंधी में उड़ा स्कूल शेड, 5 क्लास के बच्चे एक कमरे में पढ़ने को मजबूर

धमतरी। एक तरफ नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को प्रवेशोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ कई गांवों में स्कूलों की बदहाल तस्वीर भी सामने आ रही है। धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र के प्राथमिक शाला गेदरा में स्कूल भवन तो जर्जर है ही साथ ही टीन शेड भी उड़ चुकी है। इसके चलते कक्षा पहली से पांचवीं तक के सभी बच्चों की पढ़ाई एक ही छोटे कमरे में कराई जा रही है। इसमें भी बिजली और पंखों की सही व्यवस्था नहीं होने से मासूम छात्र-छात्राएं उमस के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, वर्ष 1958 में स्थापित इस स्कूल भवन की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई है। करीब दो-तीन वर्ष पहले मरम्मत के नाम पर खपरैल की जगह टीन शेड लगाया गया था, लेकिन हाल ही में आई तेज आंधी, तूफान और बारिश के चलते वो भी उड़ गया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल दी। भवन का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और छत पर लगे सीलिंग पंखे भी टूट गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले हुई। यदि उस समय बच्चे स्कूल में मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। उनका आरोप है कि मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। मजबूत टीन, बेहतर पाइप और सुरक्षित निर्माण होता तो यह स्थिति नहीं बनती। स्कूल भवन के असुरक्षित होने के कारण कक्षा पहली से पांचवीं तक के सभी विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षकों के सामने भी शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित करना बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्कूल भवन की तत्काल मरम्मत या नए भवन के निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि वनांचल क्षेत्र के बच्चों को भी सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अधिकार है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

स्कूल भवन के सवाल पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि भवन विहीन या जर्जर भवन वाले स्कूलों का प्रस्ताव जा चुका है। कई स्कूल का निर्माण भी करा रहे हैं। फिलहाल गेदरा का भी देखेंगे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

पैसे के विवाद में सक्ती में पेपर कटर से जानलेवा हमला: मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सक्ती। सक्ती जिला मुख्यालय में स्टेशन के पास युवक पर थर्माकोल पेपर कटर से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्णा सारथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में पैसे के विवाद के बाद गुस्से में हमला करना स्वीकार किया है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त खून से सना थर्माकोल पेपर कटर भी बरामद कर लिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत कार्रवाई की गई है। मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, 8 जुलाई की रात स्टेशन क्षेत्र में हुए विवाद के दौरान आरोपी कृष्णा सारथी ने अभय चौहान उर्फ साहिल उर्फ बोंगा के गले और सीने जैसे शरीर के अत्यंत संवेदनशील अंगों पर लगातार वार किए।

गंभीर रूप से घायल साहिल किसी तरह मौके से निकलकर पास के एक होटल में पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 और पुलिस को सूचना दी। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जांजगीर और बाद में बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। वर्तमान में उसका इलाज बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। घटना के बाद घायल की पत्नी की शिकायत पर सक्ती थाना में अपराध क्रमांक 304/2026 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। वहीं, बिलासपुर में उपचाररत घायल का कार्यपालिक दंडाधिकारी के माध्यम से मरणासन्न कथन भी दर्ज कराया गया। अपने बयान में घायल ने कृष्णा सारथी द्वारा थर्माकोल पेपर कटर से हमला किए जाने की पुष्टि की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि साहिल उससे बार-बार पैसे मांग रहा था।

पैसे नहीं देने पर दोनों के बीच विवाद और मारपीट हुई। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने जान से मारने की नीयत से थर्माकोल पेपर कटर से गले और सीने पर कई वार कर दिए। आरोपी के कब्जे से खून से सना थर्माकोल पेपर कटर बरामद कर जब्त किया गया है।

पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल के नेतृत्व में उप निरीक्षक राजेश यादव, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राहुल बाजपेयी, उप निरीक्षक पूजा यादव, प्रधान आरक्षक शब्बीर मेमन, आरक्षक भागवत श्रीवास, रामकृष्ण देवांगन, विकास राठौर, दीपक बंजारे तथा थाना सक्ती के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में छत्तीसगढ़ में रहा अव्वल

बस्तर। जिले के बकावंड विकासखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में बकावंड ब्लॉक पूरे छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर आया है। इस परीक्षा में अकेले बकावंड ब्लॉक से रिकॉर्ड 130 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। बकावंड की इस बड़ी सफलता की बदौलत अब पूरा बस्तर जिला भी इस परीक्षा के नतीजों में पूरे प्रदेश के भीतर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षा में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों के लिए आगे की पढ़ाई अब बेहद आसान हो पाएगी। चयनित विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से अगले 4 साल तक हर महीने 1-1 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस आर्थिक सहायता से ग्रामीण और गरीब परिवार के बच्चों को अपनी पुस्तकें, कॉपियां, स्टेशनरी और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी अन्य जरूरी सामग्री खरीदने में बड़ी मदद मिलेगी। बकावंड ब्लॉक को मिली इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे शिक्षा विभाग की अच्छी रणनीति और कड़ी मेहनत रही है।

आत्मानंद स्कूल के छात्र से मारपीट, तलाश में पुलिस

सक्ती। सक्ती जिले के अड़भार क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र के साथ कथित रूप से अपहरण कर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच मे आरोपियों में अधिकांश नाबालिग होने की बात सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार, आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाला नाबालिग छात्र सुबह करीब 11 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। परिजनों का आरोप है कि रास्ते में चार मोटरसाइकिलों पर सवार 8 से 9 युवकों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाकर शनि मंदिर के पीछे स्थित गौठान के पास पहुंचाया। वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने छात्र के कपड़े उतरवाकर उसके साथ लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की।

मिठाई दुकान में आग दमकल वाहन पहुंचने तक सब जलकर राख

तखतपुर। तखतपुर के प्रसिद्ध श्री गणेश कॉफी एंड स्वीट्स में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग सब कुछ तबाह कर चुकी थी। होटल का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री जलकर राख हो चुके थे, जिससे सालों की कमाई कुछ मिनटों में बरबाद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर तखतपुर में स्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। गौरतलब है कि करीब दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री ने तखतपुर में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी। हर आगजनी की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कमी का मुद्दा उठता है।

चिरमिरी की कुरासिया अंडरग्राउंड खदान में उत्पादन पूरी तरह ठप

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र की कुरासिया अंडरग्राउंड खदान में शनिवार को प्रथम पाली का उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। एकतानगर और आजाद नगर कॉलोनी में पिछले 11 दिनों से बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित रहने से श्रमिकों का आक्रोश फूट पड़ा। श्रमिक संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में मजदूरों ने उत्पादन बंद कर खदान परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रमिक खदान परिसर में एकत्रित हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के कारण प्रथम पाली में उत्पादन पूरी तरह प्रभावित रहा। श्रमिकों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं की गईं, जिससे उनके परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए एचएमएस के केंद्रीय अध्यक्ष बजरंगी शाही सहित कई श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। मजदूरों की मांगों को जायज बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की।

सरगुजा का कमाल, गोल्ड-सिल्वर-ब्रॉन्ज तीनों अपने नाम

सरगुजा। संभाग के खिलाड़ी अब अलग-अलग तरह के खेलों में भी नेशनल लेवल पर जलवा दिखा रहे हैं। मिनी गोल्फ जैसे खेल में भी सरगुजा के बच्चों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इस बार एक नहीं बल्कि तीन-तीन मेडल एक ही खेल में मिले है। मिनी गोल्फ नेशनल के अलग अलग इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लगा है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर जिले के साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय सीनियर मिनी गोल्फ प्रतियोगिता 25 से 30 जून तक रायपुर में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सरगुजा जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कई पदक अपने नाम किए साथ ही मिनी गोल्फ खेल को नई पहचान दिलाई है। प्रतियोगिता में प्रीतम जायसवाल ने डबल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं शिवानी सोनी ने सिंगल इवेंट में कांस्य पदक जीता और बृजदेव सिंह ने टीम इवेंट में रजत पदक जीता है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एलिफेंट अटैक, दो लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही है. ताजा मामला रायगढ़ का है

रायगढ़। वनांचल जिले रायगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी है। शनिवार को जंगली हाथियों के अलग अलग हमलों में दो लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस हफ्ते हाथियों के हमले में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। धर्मजयगढ़ डिवीज़न के छाल और कापू वन क्षेत्रों में सुबह-सुबह यह घटना हुई। धर्मजयगढ़ डिवीज़न के वन अधिकारी (छस्नह) जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कापू वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालगांव गांव में एक जंगली हाथी के घुसने से अफ़रा-तफ़री मच गई। इसी दौरान, गांव की रहने वाली शकुंतला बाई (37) अपने घर से बाहर भागीं और हाथी ने उन्हें मार डाला। इस हमले में पीड़िता की नाबालिग बेटी बाल-बाल बच गई। एक अन्य घटना में, छाल वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औरनारा गांव में सुबह करीब 5 बजे एक मज़दूर बंधन सिंह अगरिया (50) की भी इसी तरह एक जंगली हाथी ने जान ले ली। वह शौच के लिए घर से बाहर निकले थे। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद वन और पुलिस विभाग के कर्मचारी दोनों जगहों पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मृतकों के परिवारों को तत्काल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि बाकी मुआवज़े की राशि 5।75 लाख रुपये प्रति परिवार ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस हफ़्ते हाथी के हमलों की तीन घटनाएं सामने आई हैं। 9 जुलाई को कोरबा ज़िले के एक जंगल में जंगली मशरूम इकट्ठा करते समय एक 55 वर्षीय व्यक्ति की हाथी के कुचलने से मौत हो गई, जबकि पिछले महीने इसी ज़िले में ऐसे ही हमलों में एक 40 वर्षीय चरवाहे और एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक दशक से ज़्यादा समय से इंसान और हाथी के बीच टकराव एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। हाल के वर्षों में यह मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक भी फैल गया है। कोरबा और रायगढ़ का धर्मजयगढ़ इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके अलावा सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर और बलरामपुर ज़िलों में भी हाथियों का गांवों और खेतों में अक्सर आना-जाना होता है, जिससे लोगों की मौत और फ़सलों को नुकसान होता है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमलों में 330 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।

स्टंट करते वीडियो हुआ था वायरल 60 बाइक चालकों को पकड़ा

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर्स से हुड़दंग मचाने वाले बाइकर गैंग पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 60 बाइकों को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। इतिहास दरअसल, मैनपाट में पिछले कुछ समय से बाइकर गैंग की गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं। ये युवक समूह बनाकर सड़कों पर बेहद तेज गति से बाइक चलाते थे और पटाखों जैसी आवाज वाले साइलेंसर्स का इस्तेमाल कर पर्यटकों व स्थानीय लोगों की शांति भंग कर रहे थे। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पुलिस ने पर्यटन स्थलों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी है। कमलेश्वरपुर पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की पहचान कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिना दस्तावेज, नियमों का उल्लंघन करने और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी यह चालानी कार्रवाई जारी रहेगी।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस और युवा कांग्रेस का सांगठनिक ढाँचा पूरी तरह ध्वस्त : भाजयुमो

रायपुर। प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव पर तीखा कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा है कि इस तथाकथित चुनाव ने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र और संगठनात्मक ढाँचे की बची-खुची साख को पूरी तरह तार-तार कर दिया है। श्री टिकरिहा ने कहा कि कांग्रेस में वर्चस्व की इस जंग ने पार्टी के भीतर मचे घमासान और बड़े नेताओं के बीच की रार को सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर दिया है। टिकरिहा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्विरोध इस कदर हावी हो चुका है कि कल तक जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भक्ति में लीन रहते थे, वे ही आज उनके सामने ताल ठोककर खड़े हैं। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव द्वारा बघेल समर्थित प्रत्याशी के विरोध में अपना उम्मीदवार उतारना यह साबित करता है कि कांग्रेस के भीतर अंदरूनी सत्ता-संघर्ष और आधिपत्य की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। श्री टिकरिहा ने कहा कि कांग्रेस और युवक कांग्रेस में अनुशासनहीनता चरम पर है और पूरा संगठनात्मक ढाँचा ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। युवा कांग्रेस के चुनावी ड्रामे पर कड़ा प्रहार करते हुए श्री टिकरिहा ने कहा कि युवा कांग्रेस का यह चुनाव केवल और केवल पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह गया है।

रायपुर के पं. जेएनएम मेडिकल कॉलेज में 20 एमबीबीएस सीटें बढ़ीं

रायपुर। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (जेएनएम) मेडिकल कॉलेज, रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह कॉलेज पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ से संबद्ध है। एमएआरबी की ओर से 10 जुलाई 2026 को जारी अनुमति पत्र के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250कर दी गई है, यानी कुल 20 नई सीटों की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1963 में 60 एमबीबीएस सीटों के साथ स्थापित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ने समय-समय पर अपनी प्रवेश क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। प्रारंभिक 60 सीटों से बढ़कर यह संख्या 100, वर्ष 2009 में 150, वर्ष 2019 में 180, वर्ष 2023 में 230 तथा अब एनएमसी की नवीनतम स्वीकृति के पश्चात 250 सीटों तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीटों की संख्या बढने से प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और वे अपने ही राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रयासों के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।

सरस्वती सायकल योजना से संवर रहा छत्तीसगढ़ की बेटियों का भविष्य

रायपुर। सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्कूल तक आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन सरकार ने एक ऐसी पहल की है, जिससे बेटियों के हौसलों को नए पंख मिल गए हैं। शिक्षा सत्र शुरू होने के मात्र एक महीने के भीतर, जुलाई माह में ही, पात्र छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत निशुल्क सायकल का वितरण किया जा रहा है। यह त्वरित फैसला पालकों, शिक्षिकाओं और स्वयं छात्राओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो रहा है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सारंगढ़ की कक्षा 9वीं की छात्रा छोटी यादव की कहानी जिले की सैकड़ों बेटियों का प्रतिनिधित्व करती है। छोटी को अपने गांव झरपडीह से 3 किलोमीटर दूर स्कूल आने के लिए हर रोज पैदल सफर तय करना पड़ता था। तपती धूप और बारिश में पैदल चलना थका देने वाला होता था, लेकिन अब उसकी यह परेशानी दूर हो चुकी है। निशुल्क सायकल पाकर छोटी के चेहरे पर आई मुस्कान उसकी खुशी और राहत को साफ बयां करती है।

महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में एलुमिनाई एसोसिएशन की बैठक संपन्न

रायपुर। महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में एलुमिनाई एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाविद्यालय के विकास, वर्तमान विद्यार्थियों के हितों तथा आगामी गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य पूर्व छात्रों को महाविद्यालय की प्रगति एवं छात्र हितैषी योजनाओं से जोड़ते हुए उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना रहा। बैठक में आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान, सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों तथा विभिन्न छात्र कल्याणकारी गतिविधियों की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर एवं निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग प्रदान करने, उनकी फीस सहायता हेतु एलुमिनाई एसोसिएशन की सहभागिता बढ़ाने तथा इस दिशा में ठोस पहल करने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन रही है महतारी वंदन योजना : साय

मुख्यमंत्री ने जारी की महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त, 66 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डीबीटी से 626.25 करोड़ रुपये अंतरित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने

सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ लखपति दीदी जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।

पंचायतों के कार्यों में गुणवत्ता हो सर्वोच्च प्राथमिकता : विजय शर्मा

■हर स्कूल में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण के निर्देश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कमर कसकर अगले आठ महीनों में निर्धारित सभी लक्ष्यों को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा शुक्रवार को वीबी जीरामजी योजना एवं पंचायत विभाग के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) से जुड़े।

उप मुख्यमंत्री ने सभी जिला पंचायत सीईओ को अपने-अपने विकासखंडों का नियमित भ्रमण करने, निर्माण कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता और जवाबदेही आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत संतृप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्रामों में मुक्तिधाम उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मुक्तिधाम

निर्माण कराने तथा अनुपयोगी एवं खराब पड़े बोरवेलों को इंटक वेल के रूप में विकसित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

वीबी जीरामजी योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने तथा सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीबी जीरामजी योजना का लाभ तेजी से प्रत्येक ग्राम तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने वीबी जीरामजी के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र में चबूतरों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएम श्री विद्यालयों, पोटा केबिनों एवं अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण, धरसा विकास तथा शौचालय निर्माण जैसे जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए श्री शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों की समयबद्ध जियो-टैगिंग कराने तथा नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीब परिवारों के आवास निर्माण में यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने सभी जिला पंचायत भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए निर्देश दिए और जिन जिला पंचायतों में सौर ऊर्जा स्थापनाएं नहीं है वहां स्थापना करवाने तथा इसके मेंटेनेंस के लिए एनआरएलएम की दीदियों को प्रशिक्षित कर कार्य प्रदान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव श्री भीम सिंह, सचिव श्री धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक एनआरएलएम श्री अश्वनी देवांगन, संचालक पंचायत श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

'बाबा' को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग सोशल मीडिया पर पोस्टर हुए वायरल

■ टीएस सिंह देव ने कहा- सारे निर्णय हाईकमान लेता है

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आदिवासी नेता और पूर्व सांसद दीपक बैज का कार्यकाल कल यानी 12 जुलाई को खत्म होने की खबर है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि टीएस सिंह देव का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं है। सभी फैसले हाई कमान लेता है।

कई स्थानीय नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बाकायदा पोस्टर के साथ पूर्व डिप्टी सीएम टी। एस। सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है। आदिबाबा फैंस क्लब सरगुजा समेत कई नेताओं ने यह मांग की है। इस पोस्ट में लिखा है किजिसने हर परिस्थिति में संगठन का साथ निभाया, अब समय है उनके अनुभव को नई जिम्मेदारी देने का। टीएस बाबा के नेतृत्व में मजबूत कांग्रेस।

इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने कहा कि कार्यकाल समाप्त नहीं होते। दीपक बैज की भी जब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई तो कार्यकाल की कोई तारीख तय नहीं हुई थी। जब तक उनकी जिम्मेदारी है, वह अपना दायित्व निभाएंगे। इन पर फैसले हाईकमान लेता है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठने पर टीएस सिंह देव का कहना है कि कई लोग अपने मन की बात को रोक नहीं पाते, हालांकि इस तरह की मामलों में परहेज करना चाहिए। यह सारे निर्णय हाईकमान के होते हैं, जो उन्हें लेने देना चाहिए। इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट स्थिति को अनावश्यक रूप से गड़बड़ करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू, मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक

रायपुर। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन प्रात: 9 बजे से होगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन होगा। समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम में भाग लेने वाली टुकडियों के निर्धारण एवं रिहर्सल हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा पुलिस महानिदेशक के मार्ग दर्शन में सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से यातायात, पार्किंग,ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था तथा मंच/पंडाल व्यवस्था और

बैठक व्यवस्था का निर्धारण आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा की जाएगी। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण स्कूल शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। स्कूली बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रिहर्सल कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाओं कलेक्टर रायपुर द्वारा की जायेंगी।

इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में अन्य विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के निर्धारण के संबंध में शीघ्र ही निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर 7 से 15 अगस्त तक सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा।

नाली पर बनाये पाटों पर चला निगम का बुलडोजर

रायपुर। शहर मे पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद शहर की प्रमुख मार्ग जलमग्न हो गये और नालियों की सारी गंदगी और कचरा सड़कों पर आ गया। महापौर मीनल चौबे और उनके साथ निगम अफसरों की टीम सड़कों पर उतरी और शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।

नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज पंडरी के लोधीपारा चौक का जायजा लिया और नालियों पर बनाये अवैध कब्जों को हटाया। बड़ी नाली पर कब्जा कर बनाये गए लगभग 5 अवैध पाटों को तोड़कर वहाँ कब्जा कर व्यवसायरत लगभग 5-6 फल ठेले वालों को हटाकर बड़ी नाली को कब्जामुक्त करवाने एवं सफाई की बाधा दूर करने कार्रवाई की गयी। बड़ी नाली को कब्जामुक्त करवाकर छोटी पोकलेन मशीन की सहायता से बड़ी नाली की सफाई करवाई गयी। सफाई में लगभग 1 डम्पर कचरा बाहर निकला.बड़ी नाली के कब्जामुक्त होने एवं सफाई होने से अवन्ति बाई चौक एवं आसपास बारिश में जलभराव होने की समस्या का निदान हो सकेगा एवं नागरिकों को त्वरित राहत मिल सकेगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा का अवसर

मुख्यमंत्री के निर्णय का छओए ने किया स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसिएशन के महासचिव श्री विक्रम सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय तीरंदगी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका उपस्थित थे।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से 20 विभिन्न खेलों के 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने तथा उन्हें शासकीय सेवा में लाभ का अवसर प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं का रुझान और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने इसे खेल प्रतिभाओं के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा और उपलब्धियों के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, संसाधन और सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर प्रदान करने का निर्णय युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगा तथा प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा देगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का गौरव निरंतर बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने का सशक्त आधार हैं।

राम मंदिर चंदा चोरी : आस्था के नाम पर राजनीति, चढ़ावे के नाम पर लूट- कमलेश्वर पटेल

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस कार्यसमिति के मेंम्बर कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की उपस्थिति में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं। देश के कोने-कोने से गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई, अपने गहने, अपनी बचत और अपनी श्रद्धा लेकर राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आए। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने लगभग तीन दशकों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की, देश के गरीब व मध्यम वर्ग से राम के नाम पर चंदा एकत्र किया और इसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त की।

आज वही करोड़ों रामभक्त यह पूछने को मजबूर हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया?

यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं है। यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया घोर विश्वासघात है।

तीन बड़े सवाल

1. जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा?
2. अगर सब कुछ ठीक था, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए?
3. अगर कुछ गलत नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है?

अब तक सामने आए तथ्य त्यंत गंभीर हैं-

● श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं। यह स्वयं इस बात का संकेत है कि मामला सामान्य प्रशासनिक त्रुटि का नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले का है।

● ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं, जबकि ट्रस्ट की वित्तीय निगरानी, पारदर्शिता और संपत्तियों की सुरक्षा की सर्वोच्च जिम्मेदारी उन्हीं की थी।

● मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रस्ट के विशिष्ट आमंत्रित सदस्य गोपाल राव (गोपाल नगरकोटे) को हटाए जाने और उनकी स्थिति को लेकर भी गंभीर भ्रम और विरोधाभास सामने आए हैं।

● आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्णमोहन को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, जबकि उन पर पूरे प्रकरण को दबाने और लीपापोती करने के आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए जा चुके हैं।

● यह जग जाहिर है कि ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे और शीर्ष नियुक्तियों में प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से स्वयं को अलग नहीं कर सकती।

● एसआईटी अब राम मंदिर के बड़े आयोजनों के खर्चों की भी जांच कर रही है।

● 22 जनवरी 2024 की प्राण-प्रतिष्ठा पर लगभग 113 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें लगभग 8,000 अतिथि शामिल हुए।

● 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण कार्यक्रम पर लगभग 10.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

● फर्जी रसीदों, नकद चढ़ावे, लेखा-जोखा और कथित हेराफेरी के अनेक आरोप सामने आए हैं।

● छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों की जवाबदेही अब तक तय नहीं हुई है।

● यही नहीं, भाजपा-आरएसएस ने न प्रभु श्री राम के चंदे को छोड़ा और ना ही अब उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हालिया दान घोटाले ने भी यह प्रश्न खड़ा किया है कि

● कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती कि सीसीटीवी निगरानी, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर यह कथित घोटाला संभव नहीं हो सकता। टुकड़ों-टुकड़ों में इस्तीफे, छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी और सीमित कार्रवाई केवल लीपापोती का प्रयास प्रतीत होते हैं, ताकि बड़ी मछलियों तक आंच न पहुंचे।

क्या 2029 से देश में एक साथ होंगे चुनाव?

निर्मल कांत

संसद की संयुक्त समिति ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है, जिससे एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव तक पूरी तरह लागू की जा सके। यह बात समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने शुक्रवार को कही। समिति एक साथ चुनाव कराने से जुड़े विधेयकों की जांच कर रही है, पीपी चौधरी ने गोवा में समिति की दो दिवसीय बैठक के दौरान पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक जिन नागरिक समाज से जुड़े लोगों और संगठनों से राय ली गई है, उनमें से करीब 99 फीसदी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से देश को होने वाले लगभग सात लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान को कम करना इसका मकसद है। समिति ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की। चौधरी ने कहा, हमने मुख्यमंत्री और मंत्रियों से अनौपचारिक बातचीत की। वे गोवा की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने इस बात पर चर्चा की कि एक देश, एक चुनाव कैसे लागू किया जा सकता है, इसमें कौन-कौन सी चुनौतियां हैं और उन्हें इस तरह कैसे दूर किया जाए कि सभी पक्षों के लिए संतुलित और स्वीकार्य व्यवस्था बन सके। उन्होंने बताया कि समिति गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों का दौरा कर चुकी है। वहां समिति ने संविधान विशेषज्ञों, नागरिक समाज के संगठनों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों से बातचीत की। राजस्थान के पाली से भाजपा सांसद चौधरी ने कहा कि जिन लोगों से राय ली गई, उनमें बहुत बड़ी संख्या ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि करीब 99 फीसदी लोगों, खासकर नागरिक समाज और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। अब हमारा प्रयास ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसे सभी राजनीतिक दल स्वीकार कर सकें। जब उनसे पूछा गया कि इसे कब तक लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि समिति अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। इससे संकेत मिलता है कि यह व्यवस्था वर्ष 2029 के अगले लोकसभा चुनाव तक लागू हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, यदि राजनीतिक दल और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से अपने चुनावों का समय एक जैसा करने पर सहमत हो जाएं। चौधरी ने इस प्रस्ताव के आर्थिक लाभों का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के सामने रखी गई रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कोविंद समिति को दी गई एक आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, देश में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने से करीब सात लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। वहीं, यदि चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था को उतना ही फायदा हो सकता है। चौधरी ने कहा, अब चुनाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहते। यदि देश के किसी भी हिस्से में चुनाव होते हैं, तो उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है, क्योंकि आज सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि बार-बार चुनाव होने से सरकार के कामकाज में बाधा आती है। इसका असर शिक्षा पर भी पड़ता है, क्योंकि शिक्षकों को बार-बार चुनाव से जुड़े कामों में लगाया जाता है। इनमें मतदाता सूची तैयार करना, प्रशिक्षण लेना और मतदान की ड्यूटी करना शामिल है।

नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंका

नीरज कुमार दुबे

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा।

हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल भूमि सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार का समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और भविष्य की नीति तैयार करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब केवल चौकियों और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्वय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं स्थायी होती थीं और समाधान अस्थायी, लेकिन अब सरकार समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान तैयार कर रही है। देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या अध्ययन अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत जनसंख्या में हो रहे अस्वाभाविक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा, उनके कारणों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्वाभाविक कारणों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता के साथ नियंत्रण किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सबसे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक तत्काल पहुंचनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सरकार सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए आधारभूत ढांचे पर भी अभूतपूर्व निवेश कर रही है। अमित शाह ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर निवेश में चार सौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सड़कों, संचार व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा के सोलह सौ दस किलोमीटर लंबे हिस्से पर 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि छद्म युद्ध, अवैध हथियारों की आवाजाही, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित अन्य गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

साथ ही मोदी सरकार की सीमा सुरक्षा नीति केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम गांव को पहला गांव बताया है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार का मानना है कि जब सीमा पर बसे गांव समृद्ध होंगे, वहां के लोग सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगे, तभी सीमा सुरक्षा भी स्थायी रूप से मजबूत होगी।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह नई नीति भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा परिवर्तन है। अब देश केवल किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं रहेगा, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही पहचानकर उन्हें रोकने की सक्रिय रणनीति अपनाई जाएगी। घुसपैठ, छद्म युद्ध, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिये हथियार पहुंचाना, साइबर अपराध और संगठित अपराध आज एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ एकीकृत सुरक्षा तंत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण, जनसंख्या संतुलन की निगरानी, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती गांवों का विकास एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बना सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाहरी चुनौती का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में भी होगा। अमित शाह द्वारा प्रस्तुत यह नई रणनीति केवल सीमा सुरक्षा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, सामरिक शक्ति और भविष्य के भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने वाला व्यापक अभियान बनकर उभर रही है।हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह स्वयं भी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सीमा चौकियों का निरीक्षण किया, सुरक्षा बलों के साथ संवाद स्थापित किया, नियंत्रण रेखा का निरीक्षण किया, भारत-पाक सीमा के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र जाकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और महिला जवानों के लिए नई बैरकों का उद्घाटन किया।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

वस्तुतः प्रत्येक वस्तु नियम विरुद्ध लापरवाही से बरती जाने की हालत में अवश्य ही गारन्टी से पहिले भी बिगड़ सकती है और सुरक्षित रखने पर गारन्टी से भी कहीं अधिक समय तक ठहर सकती है... यह प्रत्यक्ष भी देखने में आता है। हमने संवत् 1974 में हारमोनियम खरीदा था जिसकी गारन्टी तीन साल की थी, उसे खूब बजाया गया लेकिन नियमानुकूल, वह 36 वर्ष गुजर जाने पर भी हमार पास वैसा ही काम देता रहा। हमारे मित्र पाधा जी ने भी एक तीन साल की गारन्टी की घड़ीं ली थी, मारे चाव के रात दिन उसकी पीठ का ढक्कन खोल कर बार बार देखा करते थे आखीर कुछ ही महीने बाद वह चुनेदानी हो गई। ठीक इसी प्रकार मनुष्य आयुः का परिमाण अथवा मनुष्य शरीर के टिकाऊपन की गारण्टी

अन्यून सौ वर्ष है, तथापि आयष्यवर्द्धक तत्तत् नियमों का भलीभांति पालन करने पर उसे यथेच्छ बढ़ाया भी जा सकता है और वर्तमान काल की तरह नियमविरुद्ध उच्छृङ्खल जीवन बिताने पर उसको अपने हाथों विनष्ट भी किया जा सकता है। इसलिए शतायुर्वै पुरुषः इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य्य यही है कि मनुष्यायुः का परिमाण (गारन्टी) सी वर्ष है।

यहां तक हमने जो कुछ विवेचन किया है उसका सार है कि-

(क) मनुष्य प्रयत्न करने पर दीर्घजीवी, स्वच्छन्दमृत्यु, चिरंजीवं और अमर भी बन सकता है।

(ख) वेदों में जो पुरुष को शतायु कहा है, उसका अभिप्राय केवल यही है, कि मानव जीवन की अवधि गारन्टी के तौर पर सौ वर्ष की है, परन्तु शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह यथेच्छ बढ़ घट सकती है।

(3) सामान्यतया वेदप्रयुक्त, आयुष्यविषयक शत और सहस्र शब्द का मुख्य अर्थ बहुत है।

क्रमशः ...

विश्व पेपर बैग दिवस

दयानिधि

विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह दिन पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। नष्ट न होने वाले प्लास्टिक बैग के विपरीत, पेपर बैग पर्यावरण के अनुकूल होता हैं।

आज, लाखों लोग अपनी खरीदारी के लिए कागज के थैलों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का व्यापक उपयोग और पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव जो हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कागज के थैले हमारी कैसे मदद करते हैं?

सबसे पहले, कागज बायोडिग्रेडेबल या आसानी से नष्ट हो जाता है, जो इसे प्लास्टिक के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है।

पेपर बैग भी कच्चे माल से बने होते हैं, जो एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। इससे हमारे पर्यावरण को भी थोड़ी राहत मिलती है। पेपर बैग काफी टिकाऊ भी हो सकते हैं (सिवाय जब वे गीले हों) और अब वे कम से कम और टिकाऊ पैकेजिंग को लोकप्रिय बनाने वाले उच्च-स्तरीय ब्रांडों की बदौलत अधिक आकर्षक दिखने लगे हैं। तो वास्तव में, पेपर बैग के बारे में ऐसा क्या नहीं है जो आपको पसंद न आए।

पेपर बैग दिवस मनाना मात्र एक साधारण थैले को पहचानने से कहीं बढ़कर है, यह नवाचार, स्थिरता और छोटे-छोटे निर्णयों को महत्व देने का अवसर है जो एक स्वस्थ पृथ्वी में योगदान दे सकते हैं। यह दिन अधिक टिकाऊ होने की दिशा में निरंतर प्रयास का सम्मान करता है।

जैसे-जैसे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमारी चेतना बढ़ती है, पेपर बैग उन छोटे-छोटे निर्णयों का स्थायी प्रतीक बन जाता है जो हम अधिक पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए कर सकते हैं। यह दिन पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग के उपयोग के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है।

पेपर बैग दिवस के इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी से शुरू होता है जब फ्रांसिस वोले ने 1852 में पहली पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया था। उनके आविष्कार ने पेपर बैग के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाया जिसके कारण उनका व्यापक उपयोग हुआ। जैसे-जैसे प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ी, लोगों ने पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को चुना और इस तरह पेपर बैग एक लोकप्रिय टिकाऊ विकल्प बन गए।

हालांकि 20वीं सदी में, प्लास्टिक बैग अपनी सुविधा और किफायती होने के कारण लोकप्रिय हो गए। दुर्भाग्य से, प्लास्टिक बैग के पर्यावरणीय प्रभाव समय के साथ और अधिक स्पष्ट हो गए, जिससे पेपर बैग में नए सिरे से रुचि पैदा हुई। स्टिलवेल के आविष्कार के बाद से पेपर बैग में कई बदलाव हुए हैं।

पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक परीक्षा

समीर भट्टाचार्य

अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्ष में हुई बढ़ोतरी पश्चिम एशिया की भू-राजनीति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देती है। यह स्थिति जितनी चिंताजनक है, उतनी ही गंभीर भी है। शुरुआत में पश्चिम एशिया का यह टकराव एक सीमित सैन्य संघर्ष जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब यह एक व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव, ऊर्जा आपूर्ति और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन का भविष्य शामिल है। वॉशिंगटन और तेहरान द्वारा हाल ही में एक-दूसरे पर किये गये हमलों ने यह उम्मीद समाप्त कर दी है कि जून के मध्य में हस्ताक्षरित सहमति पत्र स्थायी शांति का आधार बनेगा।

इसके बजाय, यह क्षेत्र फिर से एक लंबे संघर्ष के कगार पर खड़ा है, जिसके परिणाम फारस की खाड़ी से कहीं आगे तक जायेंगे। जाहिर है कि शांति की जो उम्मीद बनती दिख रही थी, वह टूट रही है। अमेरिका के ताजा हमलों का लक्ष्य ईरान की सैन्य अवसंरचना थी, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल भंडार, नौसैनिक ठिकाने, तटीय निगरानी प्रतिष्ठान और लॉजिस्टिक केंद्र शामिल थे। वॉशिंगटन ने इस कार्रवाई को एक आवश्यक कदम बताया, जिसका उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था, जिससे वह होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को खतरे में डाल सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर सहित कई महत्वपूर्ण सैन्य और बंदरगाह शहरों में विस्फोटों की पुष्टि की, जिससे हमलों के पैमाने और भौगोलिक विस्तार का पता चलता है।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेजी से जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये और चेतावनी दी कि अमेरिका की किसी भी आगे की कार्रवाई का जवाब पूरे खाड़ी क्षेत्र में व्यापक प्रतिशोध के रूप में दिया जायेगा। वर्तमान संकट के

केंद्र में होर्मुज जलडमरूमध्य है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन वैश्विक तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। जून में हुए युद्धविराम ने वाणिज्यिक नौवहन को फिर शुरू तो कर दिया, पर इस मूल प्रश्न को हल नहीं कर पाया कि जलडमरूमध्य पर नियंत्रण किसका होगा। सहमति पत्र की पांचवीं धारा के अनुसार, ईरान को 60 दिनों तक वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करनी थी। हालांकि, तेहरान ने इस प्रावधान की व्याख्या इस रूप में की कि उसे अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार नौवहन को नियंत्रित करने का अधिकार है।

अमेरिका का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अधीन है और इस पर एकतरफा ईरानी नियंत्रण नहीं हो सकता। यह कानूनी विवाद अब सैन्य टकराव में बदल चुका है। जिन जहाजों को ईरान 'अनुमोदित नहीं' मानता है, उन पर हमले यह संकेत देते हैं कि वह एक नयी समुद्री व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, जिसमें वाणिज्यिक जहाज तेहरान की निगरानी में संचालित हों। वॉशिंगटन इसे नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता के लिए अस्वीकार्य चुनौती मानता है। यह संघर्ष अब केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह समुद्री प्रभुत्व और क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए एक व्यापक संघर्ष बन गया है। स्थिति को और जटिल बनाता है नाटो की अनिश्चित भूमिका। डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना की है कि वे पर्याप्त सैन्य समर्थन नहीं दे रहे हैं। वहीं नाटो महासचिव ने यूरोप के योगदान का बचाव करते हुए रक्षा खर्च और लॉजिस्टिक समर्थन में वृद्धि का उल्लेख किया। इसके बावजूद, इटली सहित कई यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है ईरान के भीतर हुआ राजनीतिक परिवर्तन। अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के साथ एक ऐसा युग समाप्त हो गया, जो सावधानीपूर्ण रणनीतिक संतुलन से परिभाषित था। नये नेतृत्व ने पहले की तुलना में अधिक आक्रामक रुख दिखाया है। इस युद्ध ने ईरान की घरेलू राजनीति को भी बदल दिया है। पहले जनता का गुस्सा मुख्य रूप से शासन के खिलाफ था, जो आर्थिक कठिनाइयों, राजनीतिक दमन और व्यापक विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित था। पर अमेरिकी और इस्राइली हमलों ने, जिनसे नागरिक अवसंरचना को नुकसान पहुंचा और नागरिक हताहत हुए, जनधारणा को बदल दिया है। इसके बावजूद, गंभीर संरचनात्मक समस्याएं बनी हुई हैं। ईरान आर्थिक प्रतिबंधों, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और शिक्षित युवाओं के पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर आइआरजीसी का बढ़ता प्रभुत्व राज्य की शक्ति को मजबूत कर सकता है, लेकिन इससे दीर्घकालिक स्थिरता की गारंटी नहीं मिलती।

किसी समझौते की संभावना दो प्रमुख मुद्दों पर निर्भर करती है-ईरान का परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन को लेकर एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचा। जब तक इन दोनों मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक युद्धविराम केवल अस्थायी विराम ही साबित होंगे। भारत के लिए यह संघर्ष तात्कालिक आर्थिक जोखिमों और दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौतियों, दोनों को प्रस्तुत करता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा फारस की खाड़ी की स्थिरता से जुड़ी हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करता है, आयात लागत बढ़ाता है और घरेलू महंगाई को बढ़ावा देता है। हाल के हफ्तों में सैकड़ों तेल टैंकर इस मार्ग से गुजरते रहे हैं, पर सुरक्षा स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। भारत के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री और मानवीय हित भी हैं।

भारतीय ध्वज वाले जहाज खाड़ी के जल में लगातार चल रहे हैं, जबकि सैकड़ों भारतीय नाविक संघर्ष क्षेत्र के पास वाणिज्यिक जहाजों पर तैनात हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रमुख कूटनीतिक व लॉजिस्टिक प्राथमिकता बन गया है। ऊर्जा के अलावा, पश्चिम एशिया भारत के व्यापार, प्रवासी समुदाय और रणनीतिक साझेदारियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नयी दिल्ली ने अमेरिका, इस्राइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाये रखे हैं। यदि संघर्ष और बढ़ता है, तो इस संतुलन को बनाये रखना और कठिन हो जायेगा। यह उभरता हुआ संघर्ष केवल वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव का एक और अध्याय नहीं है। यह पूरे क्षेत्रीय रणनीतिक ढांचे के पुनर्गठन का संकेत है। होर्मुज इस व्यापक संघर्ष का प्रतीक और युद्धक्षेत्र, दोनों बन चुका है। यह टकराव कूटनीति के माध्यम से समाप्त होगा या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जायेगा, यह आने वाले महीनों में वॉशिंगटन, तेहरान और अन्य क्षेत्रीय राजधानियों द्वारा लिये जाने वाले राजनीतिक निर्णयों पर निर्भर करेगा।

आज का इतिहास

1874 ओन्टारियो कृषि कॉलेज की स्थापना की गयी।
1912 'क्वीन एलिजाबेथ' अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी।
1917 विजिलेंस ने जबरन 1,300 हड़ताली खदान मजदूरों, उनके समर्थकों और बिसबे, एरिज़ोना, अमेरिका से न्यू मैक्सिको के निर्दोष दर्शकों को खदेड़ दिया।
1918 जापानीबटलशिप कावाची की गोला बारूद पत्रिका में विस्फोट से 600 से अधिक अधिकारी और क्रू के लोग मारे गए।
1920 सोवियत-लिथुआनियाई शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, सोवियतरसिया ने एक स्वतंत्र लिथुआनिया को मान्यता देने के लिए सहमति व्यक्त की थी।
1935 बेल्जियम ने कूटनीतिक रूप से सोवियत संघ को मान्यता दी।
1939 त्रिनिदाद और टोबैगो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई।
1943 प्रोखोरोव्का की लड़ाई हुई। यह सोवियत संघ और जर्मनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह सबसे बड़ी संख्या वाली टैंक लड़ाइयों में से एक थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ा गया था। लड़ाई सोविएत संघ की भूमि पर हुई।
1948 अरब-इजरायल युद्ध-इजरायल रक्षा बल के अधिकारी यित्जाक रबिन्स ने फिलिस्तीनियों को लोद और रामला के शहरों से निष्कासित करने का आदेश दिया।
1962 ब्रिटिश रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स ने लंदन में मार्की क्लब में अपना पहला संगीत कार्यक्रम खेला।
1963 इंग्लैंड के गॉर्टन में, 16 वर्षीय पॉलिन रीडे गायब हो गया, मूर हत्याओं में इयान ब्रैडी और मायरा हिंडले का सबसे अच्छा शिकार हुआ।
1967 यूनानी सैन्य शासन ने अपनी नागरिकता के 480 यूनानी टुकड़े किए।
1971 ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी ध्वज, ऑस्ट्रालिया के आधिकारिक झंडों में से एक, पहली बार उड़ाया गया था।
1975 साओ तोमे और प्रिंसेपी ने पुर्तगाल में स्वतंत्रता की घोषणा की
1976 बारबरा जॉर्डन एक राजनीतिक सम्मेलन के लिए सबसे पहले अफ्रीकी-अमेरिकी थे।
1979 किरीबाती यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हो गई। यह एक द्वीप देश है। यह मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। यह 33 विभिन्न प्रकार के द्वीपों और भित्तियों से मिलकर बना है। दक्षिण तरवा देश की राजधानी है।
1982 चेकर मोटर्स निगम ऑटोमोबाइल ने अपना उत्पादन बंद किया।
1986 होमोसेक्सुअल लॉ रिफॉर्म एक्ट न्यूजीलैंड में कानून बन गया, जो समलैंगिक यौन संबंध को कमजोर करता है।

विदेश से लौटते ही मोदी का एक्शन! भाजपा में क्या होने वाला है?

अभिनय आकाश

इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव की। पहले निजी सचिव अमर सिंह को हटाया गया। फिर आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार की तरफ से अभी तक इन अधिकारियों को हटाने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। आदेश जारी हुए, अधिकारी हटाए गए लेकिन कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। यही बात इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य ट्रांसफर से अलग बनाती है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रालयों और मंत्रियों के दफ्तर की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा कर रही है। जिन अधिकारियों के कामकाज को लेकर सवाल है, या जिनकी कार्यशैली सरकार की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है उन पर एक्शन हो सकता है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है। लेकिन लगातार हो रहे बदलावों ने इन अटकलों को जरूर हवा दे दिया है। चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सरकार कुछ और बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक फैसले ले सकती है।

विस्पर्स इन द कॉरिडोर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भूपेंद्र यादव को पता ही नहीं था कि उनके स्टॉफ को हटाया जा रहा है। उन्हें तब पता चला जब सचिवालय में चिट्ठी टाइप होने चली गई। अगर विस्पर्स इन द कॉरिडोर की खबर सच है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है कि मंत्री ऑफिस में भी नहीं बताया गया। शैलेंद्र यादव को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि वो बहुत पुराने वक्त से भूपेंद्र यादव के साथ थे। आरएसएस के जमाने से वो जुड़े थे। एक महीना राजनीति में बहुत लंबा वक्त होता है। भूपेंद्र यादव लुटियंस दिल्ली के जिस बंगले में रहते हैं वो बंगला नंबर 9 है। इस बंगले में आज से करीब एक महीने पहले की बात है तृणमूल कांग्रेस के सारे बागी सांसद इसी बंगले में बैठे थे।

उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि 20 की संख्या कैसे पूरी होगी। लेकिन उस बंगले से आई तस्वीर में कहीं भी भूपेंद्र यादव नजर नहीं आ रहे थे। कहा ये भी गया कि भूपेंद्र यादव लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे और

इसलिए उन्होंने सांसदों की तस्वीरें खिंचवाई और बीजेपी का आंकड़ा 300 के पार कर दिया। एक व्यक्ति जो बीजेपी को बंगाल जिताकर आया हो। जो टीएमसी को तोड़ रहा हो। उसके सारे के सारे स्टॉफ को पीएमओ के आदेश पर हटा दिया गया। दावे के अनुसार भूपेंद्र यादव को बाद में दी जा रही है।

भूपेंद्र यादव एक पॉवरफुल मंत्री हैं और बीजेपी के नंबर 2 के नेता के बहुत करीबी माने जाते हैं। संगठन के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। राजनीतिक हलकों में दबी जुबान से ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव का इस्तीफा भी हो सकता है। पीएम मोदी 12 जुलाई को अपने विदेश दौरे से लौट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम एक गोल रखते हैं और उसके पूरा होते ही दूसरा बड़ा गोल रखते हैं। पीएम मोदी एक टारगेट ओरिएंटेड लीडर हैं। वो टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट पर फिट नहीं बैठने पर पूरे घर को बदल डालो वाली नीति अपनाते हैं। 12 जुलाई को एक बैठक होने वाली है। उसके बाद बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं।

सूत्रों के हवाले से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह को आगामी राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये जिम्मेदारी दी जा सकती हैं। वहीं नितिन गडकरी के गवर्नर बनाए जाने की भी चर्चा है। इसके अलावा भी कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कैबिनेट में बदलाव तो एक हफ्ते पहले ही हो जाना था। लेकिन एनडीए की सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना है और उसके लिए नेगोसिएशन का दौर चल रहा था। कौन सा विभाग किसके पास जाए इसको लेकर ये उस वक्त छोड़ा लंबा खिंच गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक और पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस प्लांट का उद्घाटन पहले ही करना था। लेकिन जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना तो वहां मालूम चला कि आग लग गई। सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि उस वक्त दो प्रशासनिक अधिकारियों के हटाए जाने को कहा गया था। लेकिन उस वक्त भी राजनस्थान की राजनीति को दिल्ली से चलाने वाले एक बड़े नेता ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इसके बाद पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा गया। सूत्रों के अनुसार पीएमओ की तरफ से कहा गया था कि वहां पर दो पेड़ की बातचीत चल रही थी और उस पेड़ में पीपल नहीं लगना था तो जो पेड़ लगाना था वो खेजड़ी का लगाना था। लेकिन हुआ इसका उल्टा।

पौधारोपण के बाद प्रधानमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल से तस्वीरें साझा करते हुए लिखा गया कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और उन्हें पचपदरा में खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य मिला है। इस पोस्ट के सामने आते ही आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को टैग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखी। बेनीवाल ने तंज कसते हुए सवाल किया मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप राजस्थान के पचपदरा आए, वृक्षारोपण भी किया, क्या आपकी सरकार ने खेजड़ी की नई किस्म का आविष्कार किया है या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने पीपल को खेजड़ी बताकर आपसे पौधारोपण करवा दिया ? हनुमान बेनीवाल की ओर से सोशल मीडिया पर यह दावा किए जाने के बाद कि लगाया गया पौधा खेजड़ी नहीं बल्कि पीपल का है, इंटरनेट पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया। इसके कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से उस संबंधित पोस्ट और तस्वीरों को हटा दिया गया।

फिर यह पूछा गया कि जब खेजरी तय हुआ तो किसने बदला? कहा जाता है न कि जब वक्त उल्टा चलता है तो यही हो जाता है कि फिर एक के बाद एक गलतियां जो है वो सामने आने लगती है। प्लांट के अंदर पिछली बार भी बवाल मचा था। आग लगने की वजह से तो यही पूछा गया कि भाई फिर अब यह किसकी जिम्मेदारी है? फिर पेड़ वाला विवाद तो राजस्थान में भी कुछ बदलाव अगर देखने को मिल जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा।

ऑस्ट्रेलिया समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती

देवेश त्रिपाठी

प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति पर बनी सहमति बदलते वैश्विक सामरिक समीकरणों में भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता और स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास की दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से एक अहम उपलब्धि है। जिस देश ने कभी परमाणु अप्रसार के नाम पर भारत के साथ इस क्षेत्र में कोई संबंध रखने से इन्कार कर दिया था, वही आज उसे भरोसेमंद साझेदार मानते हुए उसके लिए अपने विशाल यूरेनियम भंडार खोल रहा है, तो यह भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सफलता ही है।

दरअसल, 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद कई देशों ने भारत पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे, जिससे भारत को यूरेनियम मिलना तकरीबन बंद ही हो गया था। अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते के बाद भारत को यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली। 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु समझौता हुआ, हालांकि यूरेनियम का निर्यात शुरू नहीं हो सका, जिस पर अब 12 वर्ष बाद सहमति बनी है। इस बीच, भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ती रहीं और बिजली की मांग का आने वाले वर्षों में भी बढ़ना तय है।

दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और 2070 तक नेट-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत को कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए बाध्य कर रहा है। ऐसे में, परमाणु ऊर्जा एक भरोसेमंद, स्वच्छ और दीर्घकालिक विकल्प के रूप में उभरी है। सौर व पवन ऊर्जा भी जरूरी हैं, पर उनकी उपलब्धता मौसम पर निर्भर करती है। जबकि, परमाणु ऊर्जा

चौबीसों घंटे स्थिर बिजली उत्पादन में सक्षम है। भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता अभी लगभग आठ गीगावाट है, जबकि 2047 तक इसे 100 गीगावाट का लक्ष्य पूरा करना है, जिसके लिए उसे यूरेनियम की जरूरत है। विश्व के ज्ञात यूरेनियम भंडार का करीब एक-तिहाई हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है और अब तक वह चीन, जापान, ताइवान और अमेरिका को यूरेनियम की आपूर्ति करता रहा है। अब भारत को इसमें शामिल करने की वजह दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई प्रगाढ़ता को माना जा सकता है। दरअसल, दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर क्षेत्रीय संतुलन के समर्थक हैं और यही साझा इच्छा दोनों को नजदीक लाई है।

बहरहाल, ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा, पर स्थायी आत्मनिर्भरता के लिए आयातित यूरेनियम के साथ स्वदेशी थोरियम तकनीक, घरेलू परमाणु ईंधन चक्र और अनुसंधान को भी समान गति से आगे बढ़ाना होगा। तभी यह समझौता भारत की ऊर्जा संप्रभुता का आधार बन सकेगा।

बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ असम ने छेड़ा सबसे बड़ा अभियान

नीरज कुमार दुबे

असम में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अभियान अब और तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल सीमा सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी दी है, उससे स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ रोकने के लिए चौतरफा तैयारी की जा रही है। सीमा पर कंटीली बाड़, संवेदनशील इलाकों में निगरानी, संदिग्ध घुसपैठियों की लगातार धरपकड़ और घुसपैठ कराने वाले गिरोहों की तलाश ने यह संदेश दे दिया है कि अब भारत की सीमा को हल्के में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ करने की हर कोशिश का कड़ा कानूनी जवाब मिलेगा।

हम आपको बता दें कि असम और बांग्लादेश के बीच लगभग 276 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य सरकार के अनुसार इसमें से 228 किलोमीटर से अधिक हिस्से में कंटीली बाड़ का निर्माण पूरा हो चुका है। श्रीभूमि, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा मांकाचार जिलों में सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ा है। हालांकि नदी वाले क्षेत्रों में लगभग 34 किलोमीटर से अधिक हिस्से में बाड़ लगाना संभव नहीं हो सका है। इसके अलावा श्रीभूमि जिले में कुशियारा नदी के किनारे 4.35 किलोमीटर क्षेत्र में बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल के विरोध के कारण बाड़ का निर्माण अटका हुआ है। वहां भारतीय नागरिक रहते हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है।

सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ रोकना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिन इलाकों में बाड़ लगाना संभव नहीं है, वहां आधुनिक निगरानी व्यवस्था स्थापित की गई है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं और सीमा सुरक्षा बल की 14 चौकियां लगातार वास्तविक समय में निगरानी कर रही हैं। राज्य सरकार का मानना है कि सीमा की हर गतिविधि पर नजर रखने से घुसपैठ की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि

भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के कारण कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया जटिल बनी हुई है।

राज्य सरकार ने यह भी दोहराया कि असम समझौते की धारा-6 को लागू करना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति बिप्लब कुमार शर्मा समिति की 40 महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है, जिनका उद्देश्य असम के मूल निवासियों के अधिकारों और पहचान की रक्षा करना है।

हालांकि इन सब प्रयासों के बीच असम के हैलाकांडी जिले में एक 42 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी ने सीमा सुरक्षा की चुनौती को फिर उजागर कर दिया है। पुलिस के अनुसार सिलहट निवासी यह व्यक्ति अवैध रूप से श्रीभूमि के रास्ते भारत में घुसा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उसने भारत की एक महिला से विवाह किया था और उसकी पत्नी तथा बेटी पिछले ढाई वर्षों से हैलाकांडी में रह रही हैं। पूछताछ में उसने परिवार को बांग्लादेश ले जाने की इच्छा जताई है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि उसने किस रास्ते से सीमा पार की और किन लोगों ने उसकी मदद की। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सीमा पार कराने वाले संगठित गिरोह अब भी सक्रिय हैं।

इसके अलावा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 11 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़े जाने की घटना भी बेहद गंभीर है। सभी संदिग्ध चेन्नई जाने की तैयारी में थे। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि वे मेघालय के तुरा क्षेत्र से भारत में दाखिल हुए और उन्हें सीमा पार कराने में एक बिचौलिए की भूमिका हो सकती है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं ताकि अवैध घुसपैठ के पीछे काम कर रहे एजेंटों और सहयोगियों तक पहुंचा जा सके।

देखा जाये तो असम में चल रही कार्रवाई यह स्पष्ट कर रही है कि सीमा सुरक्षा केवल बाड़ लगाने का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिक संतुलन और कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है। जो लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि हर रास्ते पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। घुसपैठ कराने वाले गिरोहों, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों और सीमा पार करने वालों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं रहेगा। भारत की सीमा का सम्मान करना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अवैध घुसपैठ करने वालों के लिए अब कानून का शिकंजा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है।

हम आपको यह भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा को बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सबसे कड़ा रुख अपनाने वाले नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों की पहचान, गिरफ्तारी और उन्हें भारत से बाहर भेजने की मुहिम को लगातार तेज किया है। इसी सप्ताह उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि असम में एक लाख बहत्तर हजार से अधिक अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा चुकी है और उनमें से लगभग इकतीस हजार को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। सीमा पर कड़ी निगरानी, आधार जारी करने के नियम सख्त करना, असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने पर जोर और सीमा पर बाड़ निर्माण में तेजी जैसे फैसलों को भी उनकी इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरमा लगातार यह कहते रहे हैं कि असम किसी भी अवैध घुसपैठिए की शरणस्थली नहीं बन सकता और राज्य की जनसंख्या, सुरक्षा तथा मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के दायरे में रहकर हर संभव कदम उठाया जाएगा। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और व्यापक होती दिखाई दे रही है।

उपचुनाव: बिहार-मध्यप्रदेश में उम्मीदवार चयन पर उठे सवाल

सत्येंद्र प्रताप सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे दो बड़े राज्यों में पहली बार अपना मुख्यमंत्री देने का राजनीतिक कीर्तिमान बनाया। इससे संगठनात्मक नेतृत्व की उनकी क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। लेकिन उसी नेतृत्व के सामने अब बिहार के बांकीपुर और मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव चुनौती बनकर उभरे हैं।

बिहार के बांकीपुर में नामांकन के बाद उम्मीदवार बदलना पड़ा, जबकि मध्यप्रदेश के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने से पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया। ऐसे में बड़ी चुनावी सफलताओं के बाद उपचुनावों में सामने आई ये मुश्किलें नितिन नवीन की संगठनात्मक रणनीति की भी परीक्षा बन गई हैं।

नितिन नवीन के सामने अब पहली बड़ी चुनावी परीक्षा बिहार और मध्यप्रदेश के उपचुनाव हैं। यह परीक्षा केवल दो विधानसभा सीटों पर जीत-हार की नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक निर्णयों की भी है। चुनावी राजनीति में उम्मीदवारों का चयन सबसे कठिन और संवेदनशील प्रक्रिया माना जाता है।

एक गलत फैसला न केवल चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है, बल्कि संगठन के भीतर असंतोष भी पैदा कर सकता है। फिलहाल भाजपा को दोनों राज्यों बिहार और मध्यप्रदेश में इसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा का परंपरागत गढ़ रही है। 1995 से यह सीट लगातार भाजपा के पास है और नितिन नवीन स्वयं भी इसी सीट से कई बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई और उपचुनाव की नौबत आई।

भाजपा ने पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अभिषेक कुमार सिन्हा (बंटी) को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए

अपना नामांकन वापस ले लिया।

इसके बाद भाजपा को तत्काल नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। नामांकन के बाद उम्मीदवार बदलना किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए असामान्य स्थिति मानी जाती है और इसने पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बांकीपुर का मुकाबला इसलिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है क्योंकि यहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को दोबारा मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट केवल अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखने का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई है।

मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा का फैसला भी विवादों में है। पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री और तीन बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने के बजाय आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद मिश्रा समर्थक खुलकर विरोध में उतर आए। दतिया में प्रदर्शन हुए, राजमार्ग जाम किया गया और स्थानीय संगठन में असंतोष खुलकर सामने आया। कुछ स्थानीय पदाधिकारियों ने इस्तीफे तक दे दिए।

नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक दतिया की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार के बाद यह माना जा रहा था कि उपचुनाव उनके लिए वापसी का अवसर होगा। लेकिन पार्टी ने पीढ़ीगत बदलाव और नए नेतृत्व पर दांव लगाया, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष पैदा हो गया।

उपचुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में स्थानीय समीकरण अधिक प्रभावी होते हैं। उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, जातीय-सामाजिक संतुलन, संगठन में उसकी स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं का उत्साह परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए टिकट वितरण में हुई छोटी-सी चूक भी बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है।

नितिन नवीन के सामने चुनौती केवल चुनाव जिताने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि उम्मीदवार चयन के कारण संगठन में असंतोष न फैले। बांकीपुर और दतिया की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा जैसी मजबूत संगठनात्मक पार्टी में भी टिकट वितरण सबसे कठिन राजनीतिक निर्णयों में से एक है।

भाजपा ने नितिन नवीन को ऐसे समय संगठन की कमान सौंपी है, जब पार्टी कई राज्यों में विस्तार और अपनी राजनीतिक बढ़त बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में बिहार और मध्यप्रदेश के उपचुनाव उनके नेतृत्व की पहली वास्तविक परीक्षा बन गए हैं।

यदि पार्टी दोनों राज्यों में राजनीतिक असंतोष को नियंत्रित करते हुए जीत दर्ज करती है, तो यह नितिन नवीन की संगठनात्मक क्षमता पर मुहर होगी। लेकिन यदि टिकट वितरण ही चुनावी नुकसान का कारण बनता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके शुरुआती कार्यकाल पर सवाल भी उठ सकते हैं।

यही कारण है कि ये उपचुनाव महज दो राज्यों बिहार एवं मध्यप्रदेश के दो विधानसभा सीटों बांकीपुर एवं दतिया की ही लड़ाई नहीं हैं, बल्कि भाजपा के नए राष्ट्रीय नेतृत्व की निर्णय क्षमता और संगठनात्मक कौशल की भी अहम परीक्षा है।

पश्चिम एशिया संघर्ष: अब युद्ध या युद्धविराम?

हरि वर्मा

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सुपुर्द-ए-खाक हो गए। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी फिर भड़क उठी है। दोनों के बीच 107 दिनों के संघर्ष के बाद 60 दिनों के लिए जो युद्ध विराम की अंतरिम शांति सहमति बनी, उस पर महज 21 वें दिन ही विराम लग गया। दोनों के हितों के टकराव पहले दिन से ही सामने आने लगे थे लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 60 दिनों में बात कुछ हद तक बन जाएगी और फिर आगे का रोडमैप तैयार होगा। ऐसा नहीं हो सका। खामेनेई की जनाजा यात्रा के दौरान ही दोनों ने एक-दूसरे का भरोसा तोड़ दिया और अब ऐसा लगता है कि उनमें 20-21 दिनों के भीतर रत्ती भर बात नहीं बनी। घटनाक्रम के हिसाब से ईरान ने तीन जहाजों पर हमले कर ताजा संकट पैदा किया।

ईरान का आरोप है कि शांति सहमति के हिसाब से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही का उल्लंघन हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के हमले के बाद बदले की कार्रवाई की। ईरान के हमले की अपनी वजह है। खामेनेई की जनाजा यात्रा के दौरान ईरान में अमेरिका और ट्रंप से बदले की कार्रवाई का जनाक्रोश साफ दिखा। मातम मना रही वहां की अवाम ट्रंप से किसी कीमत पर शांति समझौते के खिलाफ थी। श्रद्धांजलि के लिए उमड़े जनसैलाब ने ट्रंप विरोधी नारे लगाए। वहां के लोगों में प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। युद्ध के दौरान बड़ा नुकसान झेलने के बाद ईरान की माली हालत डगमगा चुकी है। उसे होर्मुज जलडमरूमध्य पर से पकड़ ढीली पड़ने का डर सता रहा है। तंगी झेल रहे ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर कब्जे जमाकर सेवा कर (टोल) वसूलने का मंसूबा पाल रखा है। ऐसे में वहां उपज रहे जनाक्रोश को थामने के लिए ईरान और वहां की रिवोल्यूनरी गार्ड (आईआरजीसी) को खामेनेई की मातमपुर्सी जैसा मौके मुफीद लगा। ताजा हमले के जरिये ईरान ने अपनी अवाम को यह संदेश देना चाहा कि वह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेक रहा और होर्मुज पर कब्जे व अमेरिका से अपनी आर्थिक क्षतिपूर्ति (भरपाई) की शांति सहमति पर अमल करा कर देश की आर्थिक हालत कुछ सुधार लेगा। इस संदेश में अवाम की भलाई दिखी। ताजा हमले में ईरान ने 85 तो अमेरिका ने 90 ठिकानों को तबाह किया। इस संघर्ष में एक-दूसरे को तो नुकसान पहुंचा ही लेकिन इससे भारत समेत समूची दुनिया अछूती नहीं रही। अमेरिका ने ईरान का वैश्विक बाजार में कच्चा तेल बेचने का लाइसेंस रद कर दिया। दुनिया की कुल आपूर्ति का पांचवा हिस्सा ईंधन (तेल-गैस) बरास्ते होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान से मिलता है।

अब ताजा हमले के बाद कई देशों के जहाज बैरंग लौटने लगे हैं। 24 घंटे के भीतर कच्चे तेल की कीमत में 5-6 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। दुनिया के बाजार लुढ़क गए। भारत में पहले दिन सेंसेक्स में करीब 1700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। दूसरे दिन जब अमेरिकी सेना का बयान आया कि हमले पूरे हो गए तो फिर बाजार में आंशिक रौनक लौटी। ईरान के हमले की एक वजह यह भी है कि खामेनेई के 37 साल के शासन की विरासत पर तीखा विवाद चल रहा है। खामेनेई की जनाजा यात्रा के दौरान अपने पिता की मृत्यु के एक सप्ताह बाद धार्मिक सभा द्वारा सर्वोच्च नेता घोषित किए गए मोजतबा खामेनेई नजर नहीं आए। चर्चा है कि वह उसी दौरान हमले में घायल हो गए थे। अब खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक हो जाने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब युद्ध होगा या फिर से युद्धविराम।

युद्ध विराम के मध्यस्थ पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में होगी। तुर्किये में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साफ कर चुके हैं कि ईरान से बातचीत बेमानी और समय की बर्बादी है। उन्होंने यहां तक कहा कि अब युद्ध विराम खत्म हो चुका है। हालांकि एक उम्मीद उन्होंने यह जगा रखी है कि बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। इधर ईरान की ओर से गालिबाफ ने अमेरिका को धौंस न जमाने की नसीहत दे डाली है। बयानों के हमले के साथ एक-दूसरे पर हमले भी जारी हैं। अब बुशहर परमाणु पावर प्लांट के पास फिर अमेरिकी मिसाइल गिरी है। बहरीन और जॉर्डन में बार-बार अलर्ट सायरन बज रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ने फिर एक-दूसरे पर दबाव की रणनीति के तहत ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए हैं। भारत समेत प्रभावित खाड़ी देश और दुनिया उम्मीद कर रही है कि विवादों का हल बातचीत से हो। ताजा हालात के बीच उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देश पहले आपस में भरोसा कायम करें। एक-दूसरे पर हमले रोकें। बातचीत का रास्ता खोले।

यह इसलिए भी जरूरी है कि इस संघर्ष से उपजे संकट के बादल को दुनिया 100 दिन से ज्यादा झेल चुकी है। ऊर्जा संकट झेल चुकी दुनिया ठीक से उबर नहीं पाई और ताजा संघर्ष ने समूचे पश्चिम एशिया के सामने फिर संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि अब युद्ध नहीं, युद्ध विराम हो।

हेल्थ नॉलेज

ऊंचाई पर जी मिचलाने की बीमारी को पहचानें...

अधिक ऊंचाई का रोग मनुष्यों को ऊंचे स्थानों पर होने वाला प्रभाव है जो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण होता है। इसे एएमएस यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ऊंचाई का रोग,अल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपोबारोपेथी, द अल्टीट्यूड बेंड्स या सोरोची भी कहा जाता है। सामान्यतया यह 2,400 मीटर यानी 8,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर होता है। यह मुख्यत: पर्वतारोहियों, ऊंचाई पर चलने या चढ़ने वालों, स्कीइंग करने वालों या यात्रियों को प्रभावित करता है। वायुमंडलीय दबाव में होने वाली कमी सांस लेना कठिन बनाती है। रोग के अधिकतर मामले हलके होते हैं। यदि आप नीचे उतर आएं तो लक्षण जल्दी ठीक हो जाते हैं।

जांच और परीक्षण

डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप के प्रयोग से किये जाने वाले शारीरिक परीक्षण में फेफड़ों से चटकने की आवाज मिल सकती है। यह आवाज फेफड़ों में तरल पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है। अन्य जाँचों में रक्त परीक्षण, मस्तिष्क सीटी स्केन, छाती का एक्स-रे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) आदि हैं।

ये सावधानियां जरूरी

3000 मीटर से अधिक या जिस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की पूर्णता की मात्रा तेजी से गिर जाये, वह गर्भवती महिला के लिए उचित नहीं है। अधिक ऊंचे स्थानों पर, शरीर की बढ़ी हुई सहानुभूतिपरक प्रक्रिया से रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, किन्तु यह हानिकारक स्तर तक नहीं पहुंचती। इसलिए ऊंचे स्थानों पर लोगों को अपने रक्तचाप की दवाएं लेते रहना चाहिए। ऊंचे-स्थान पर रक्तचाप वृद्धि का संभावित कारण शरीर की एड्रीनर्जिक गतिविधि हो सकती है, इसलिए लक्षण वाले रोगियों या अस्थिर रक्तचाप वाले रोगियों को एंटी-एड्रीनर्जिक दवा दी जाती है। यात्रा के कुछ सप्ताह पूर्व से अपनी दवा लेना शुरू कर देना और यात्रा के दौरान स्फिग्मोमेनोमीटर रखना उत्तम होता है।

दवा के दुष्प्रभाव

एसिटामोलामाईड कभी-कभी ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए बचाव की औषधि के रूप में प्रयोग होता है। यह आपकी ऊंचाई के प्रति अनुकूलन को बढ़ा देता है किन्तु ऊंचाई की बीमारी होने से नहीं रोकता। एसिटामोलामाईड लेने के बाद कुछ लोगों को झुनझुनी का अनुभव (खासकर अपने पैरों, हाथों और चेहरे पर) होता है और बार-बार मूत्रत्याग की आवश्यकता महसूस होती है। अन्य संभावित दुष्प्रभावों में उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना, और दस्त हैं। एसिटामोलामाईड गैस युक्त पेयों का स्वाद भी बदल सकता है, और कभी-कभी लोगों को चकत्ते उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक ऊंचाई के मार्गों पर बवासीर आम समस्या है, इलाज में गर्म सिंकाई, हाइड्रोकार्टिसोन ऑइंटमेंट का प्रयोग, और कब्ज से बचने के तरीके आदि आते हैं।

स्पा मैनेजर के लिए

क्या है जरूरी योग्यताएं

वर्तमान समय में, युवा पारंपरिक नौकरियों की बजाय कुछ नए क्षेत्रों में अपना हाथ आजमा रहे हैं। आज बच्चे सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनने की चाह नहीं रखते हैं, बल्कि वे योगा इंस्ट्रक्टर या जिम ट्रेनर बनके लोगों की हेल्थ संवार रहे हैं। अगर आप भी कुछ हटकर करना चाहते हैं और आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है। साथ ही आपमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं तो आप बतौर स्पा मैनेजर बनकर अपना उज्ज्वल भविष्य देख सकते हैं।

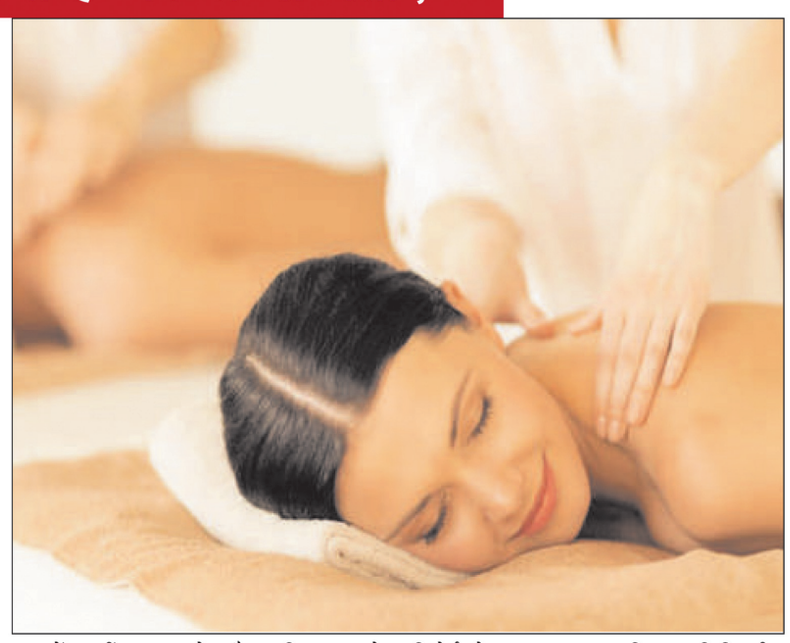

क्या होता है काम

एक स्पा मैनेजर का काम पूरे स्पा को बेहतर तरीके से संभालना होता है। इसके लिए उसे स्टाफ पर नजर रखने के अतिरिक्त आर्डर की सप्लाई, क्लांइट्स को अच्छी सर्विस देना व स्पा में अधिक से अधिक लोगों को सर्विस लेने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसके अतिरिक्त वह स्पा के लिए कुछ मार्केटिंग एक्टिवटीज व मार्केटिंग प्लानिंग में भी हिस्सा लेता है। वहीं स्पा मैनेजर स्पा के बजट को ध्यान में रखकर अपना कार्य करता है व साप्ताहिक वर्क शेड्यूल भी तैयार करता है। अपने यहां कार्यरत लोगों की एबिलिटी को निखारने के लिए वर्कशॉप आर्गेनाइज कराना भी उसके ही कार्य का एक हिस्सा होता है।

स्किल्स

अगर आप अपने क्षेत्र में सफलता की नई उंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपके भीतर कुछ गुणों का होना बेहद आवश्यक है। मसलन, आपका कंप्यूटर सेवी, स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल व इंटरपर्सनल स्किल भी बेहतर होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको पूरे स्पा को मैनेज करना होता है, इसलिए आपके भीतर आर्गेनाइजेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। आपको न सिर्फ अपने यहां कार्यरत लोगों की क्षमताओं को पहचानना आना चाहिए, बल्कि उनकी क्षमताओं के हिसाब से बेहतर काम करवाना भी आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। साथ ही आपको स्पा इंडस्ट्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। चूंकि अपने काम के दौरान आपको अलग-अलग प्रकार के लोगों से मिलना व उन्हें कन्वींस करना होता है, इसलिए आपको हर तरह के लोगों को डील करना आना चाहिए।

योग्यता

इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे छात्र मैनेजमेंट, हयूमन रिर्सोसेज या इससे संबंधित कोर्स में बैचलर डिग्री प्राप्त करके नौकरी की तलाश कर सकते हैं। अगर आप चाहें इन कोर्सेस में पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं लेकिन अधिकतर जगहों पर नौकरी के लिए बैचलर डिग्री ही पर्याप्त होती है। इसके अतिरिक्त आप स्पा मैनेजमेंट या हयूमन रिसोर्सेज आदि कोर्सेस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं।

संभावनाएं

जिस प्रकार लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं, उसे देखते हुए हर शहर में जिम एंड स्पा फैसिलिटी शुरू हो गई है। जिसके कारण स्पा मैनेजर की जॉब को भी एक नई ग्रोथ मिली है। एक स्पा मैनेजर पार्ट टाइम, फुल टाइम या कॉन्टैक्ट बेसिस पर भी काम कर सकता है। स्पा मैनेजर की आवश्यकता होटल रिसोर्ट, हेल्थ क्लब, क्रूस शिप या चिकित्सीय सैलून आदि में जॉब की संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। एक स्पा मैनेजर विदेशों में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है।

आमदनी

एक स्पा मैनेजर की सैलरी उसके अनुभव व संबंधित संस्थान पर भी काफी हद तक निर्भर करती है। फिर भी शुरूआती रूप से दस हजार से पंद्रह हजार रूपए आसानी से कमाए जा सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- अन्नाबेल स्पा इंस्टीट्यूट, केरल
- हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी, गुजरात
- गंगा स्पा एंड सेलोन एकेडमी, अहमदाबाद
- आईएसटीएचएए-स्पा एंड आयुर्वेद एकेडमी, विभिन्न केन्द्र
- प्योरटच स्पा एकेडमी, केरल
- इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्थेटिक्स एंड स्पा, महाराष्ट्र

अपने पुराने स्मार्टफोन को इन तरीकों से बनाएं सिक्योरिटी कैमरा

आजकल लोग हर दो-तीन साल में अपने फोन को अपग्रेड करते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने फोन का कोई खास इस्तेमाल नहीं रह जाता है। अगर पुराने फोन का कैमरा सही स्थिति में हो तो उसका इस्तेमाल सीसीटीवी या फिर सिक्योरिटी कैमरे की तरह भी किया जा सकता है। इस तरह आप अपने घर, ऑफिस, बच्चों या फिर पेट्स से दूर रहने के बावजूद उन पर नजर रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे

ऐसे करेगा काम

इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या एप स्टोर से 'सिक्योरिटी कैमरा' एप को डाउनलोड कर लें। आपको बता दें कि यह एप एंड्रायड और OS दोनों पर काम करेगा।

ऐसे करें इस्तेमाल

1. सबसे पहले 'सिक्योरिटी कैमरा' ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें।
2. ऐप डाउनलोड होने के बाद यूजर्स से उसके गूगल अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी। यूजर अपनी गूगल अकाउंट की डिटेल को ऐप में सबमिट करें।
3. यूजर्स को अपना नाम और पासवर्ड भरने के बाद एंटर करे। अब आपको दो ऑप्शन 'कैमरा और व्यूअर, नजर आएगा।
4. इसमें अब कैमरा ऐप क्लिक करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
5. कैमरा ऐप को सिलेक्ट करने के बाद आपके फोन में अपने आप कैमरा चालू हो जाएगा। अब कैमरा व्यूअर क्लाइंट का वेट करेगा।
6. हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन यूजर स्क्रीन व्यू को भी सिलेक्ट करे।
7. अब स्मार्टफोन का कैमरा ब्लैंक या फिर विजिबल मोड में जा सकता है।
8. अगर आप ब्लैंक स्क्रीन विकल्प को चुनते है तो स्मार्टफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान ऑफ रहेगी।
9. अब आप अपने कैमरे के जरिए बैकग्राउंड की स्ट्रीमिंग (लाइव वीडियो) भी की जा सकती है।
10. अब आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां से वीडियो सही से हो सके।

नोट: फोन को चार्जर से कनेक्ट करके ही रखे। फोन के बंद हो जाने की स्थिति में रिकॉर्डिंग को नहीं देखा जा सकता। इसलिए लगातार फोन को चेक करते रहें।

कान में झुमका फेदर वाला...

इयररिंग्स की बात करें तो बड़े-लटकते डैंजलर्स या झुमकी के साथ-साथ जब हमारी नजर फेदर इयररिंग्स, स्टड्स या बीडेड टॉप्स पर जाती है तो मन खुश हो जाता है। ये वजन में हल्के होने के साथ ही मल्टीकलर में भी मिलते हैं।

कुछ साल पहले मोर पंख वाले इयररिंग्स बाजार में भरे हुए थे। जींस पहनी हो या कॉटन की साड़ी, ये खूब जमते थे। मोर पंख वाले इयररिंग्स से आगे निकलकर अब रंग-बिरंगे फेदर इयररिंग्स बाजार में दिख रहे हैं। हर रंग और आकार में उपलब्ध ये इयररिंग्स बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखते हैं। आप इन्हें किसी भी ड्रेस के साथ पहन लें, यह अच्छे दिखते हैं। इन दिनों तो ब्लैक मेटल के टॉप्स के साथ फिक्स फेदर वाले इयररिंग्स नए आए हैं, जिन्हें वेस्टर्न ड्रेसेज के साथ खूब पहना जा रहा है। यहां तक कि कॉकटेल ड्रेस के साथ बोल्ड रंगों में फेदर इयररिंग्स को सेलिब्रिटीज भी खूब पहन रहे हैं। इनमें तो इतने लंबे इयररिंग्स भी फैशन में इन हैं, जो कान से नीचे लटक कर टॉप पर सामने की ओर आ रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने को उत्सुक हैं।

इयर कफ्स

इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से लेकर बॉलीवुड हीरोइन्स इस ट्रेंड को बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही हैं। रिहाना से लेकर एमा वाटसन और सोनम कपूर से काजोल ने इयर कफ्स को खूब जमकर पहना है। ड्रैगन से लेकर स्नेक, इजिप्शियन मोटिफ से लेकर स्पाइक और हैंजलर्स आपकी पर्सनालिटी को निखार देंगे। कॉकटेल ड्रेस के साथ फेदर्ड इयर कफ काफी अच्छे लगते हैं। जींस और टी- शर्ट कॉम्बो के साथ एक ही कान में इयर कफ पहनें। पारंपरिक परिधानों के साथ इजिप्शियन मोटिफ वाले इयर कफ अच्छे लगेंगे।

मल्टीकलर टॉप्स

टॉप्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। इन्हें बड़े भी पहनते हैं और अच्छे दिखते भी हैं। मल्टीकलर में कई डिजाइन के टॉप्स बाजार में छाए हुए हैं। फ्लावर पावर देखना हो या एनिमल्स का जादू, एजटेक प्रिंट की बात हो या पोल्का डॉट्स की, टॉप्स पर ये सारे डिजाइन छाए हुए हैं। जींस टॉप पर तो ये बेमिसाल दिखते हैं, कुर्ती के साथ पहनने के लिए किसी ने मना तो नहीं किया है।

हर रंग में स्टड्स

स्टड्स यूं तो व्हाइट स्टोन में ही कमाल के दिखते हैं लेकिन इन दिनों हर रंग और कट में स्टड्स मिलने लगे हैं। इन्हें आप पारंपरिक परिधानों के साथ ही वेस्टर्न ड्रेसेज के साथ पहन सकती हैं। व्हाइट के अलावा, ब्लैक, पिंक, पीच, नीला जैसे रंग स्टड्स के लिहाज से हॉट पसंद हैं। कॉकटेल ड्रेसेज के साथ तो स्टड्स से बेहतरीन कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है। बाल को बांध लें और बड़ा सा स्टड्स कानों में पहन लें, आपकी स्मार्टनेस का कोई जवाब नहीं होगा।

क्या है एक्सपायरी डेट का सच...?

बाजार से खरीदी जाने वाली लगभग हर चीज पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट लिखी होती है, साथ ही कई निर्देश भी। क्यों अंकित की जाती है एक्सपायरी डेट...क्या आपको पता हैं इन निर्देशों का मतलब? इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरुर रखना चाहिए

जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ उसकी एक्सपायरी डेट पर होता है। लेकिन कुछ मैसेज इससे भी जरूरी हो सकते हैं, जिन्हें आपको समझना होगा। एक्सपायरी डेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण..होती है, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों एवं दवाईयों के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के लिए। लेकिन हर चीज सिर्फ एक्सपायरी डेट तक ही सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है। एक्सपायरी डेट, वस्तुओं पर हमारी सुरक्षा के लिहाज से अंकित की जाती है, लेकिन अन्य निर्देशों को समझने का तरीका पता होना भी हमें जरूरी है।

पदार्थों की फ्रेशनेस

एक्सपायरी डेट एक अनुमान के मुताबिक डाली जाती है, जिसका संबंध खाद्य पदार्थों की फ्रेशनेस से होता है, यह जरूरी नही कि उनका संबंध सुरक्षा से ही हो। खाद पदार्थों की पैकिंग पर विक्रय की तारीख भी अंकित होती है, जो कि विक्रेताओं के लिए होती है। यह एक तरह की गाइडलाइन है, कि इस तारीख तक कि विक्रेता, संबंधित उत्पाद को बेच सकते हैं। कई उत्पादों पर बेस्ट इफ यूज्ड बाय डेट भी डली होती है, जिसका मतलब होता है, नीयत तारीख तक प्रयोग करने पर संबंधित वस्तु की गुणवत्ता और स्वाद बरकरार रहेगा। बेकरी उत्पादों पर गारंटीड फ्रेश डेट का होना दर्शाता है, कि संबंधित दिनांक तक उत्पाद का स्वाद और फ्रेसनेस बरकरार रहेगी। लेकिन इस दिनांक के बाद इनमें परिवर्तन आ सकता है। जरूरी नहीं है, कि वह उत्पाद उस दिनांक को एक्सपायर हो। एक्सपायरी डेट एकमात्र उत्पाद की सुरक्षा से संबंधित विकल्प है। इस डेट की सीमा पार हो जाने पर बेशक आपको संबंधित उत्पाद को फेंक देना चाहिए। जब भी कोई सामान खरीदें, हर तरह से पड़ताल करें। लेकिन किसी भी प्रकार का संशय होने की स्थिति में उस उत्पाद का प्रयोग बिल्कुल न करें।

रेसिपी

पनीर सैंडविच

सामग्री

ब्रेड स्लाईस आवश्यकतानुसार, आलू (उबले हुए), थोड़ा मक्खन, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच काली मिर्च, एक हरी मिर्च, पनीर की स्लाईस, एक चम्मच घी, बारीक कटे हुए टमाटर

विधि

पनीर सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में उबले हुए आलू को मैश कर लें और उसमें नमक,काली मिर्च,हरी मिर्च,टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर ले। इसके बाद ब्रेड स्लाईस के ऊपर थोड़ा मक्खन लगाकर, आलू के तैयार मिश्रण को इसके ऊपर डालकर फिर पनीर की स्लाईस रख दें और इसके ऊपर ब्रेड स्लाईस रख दे। अब टोस्टर को गर्म करके उसमें थोड़ा घी लगा दें और उसमें यह सभी ब्रेड स्लाईस रख दे। कुछ समय के बाद इन्हें निकाल ले। अब तैयार है आपके गर्मागर्म सैंडविच।

इन छोटी-छोटी बीमारियों को झट दूर करेगा यह जादुई नुस्खा

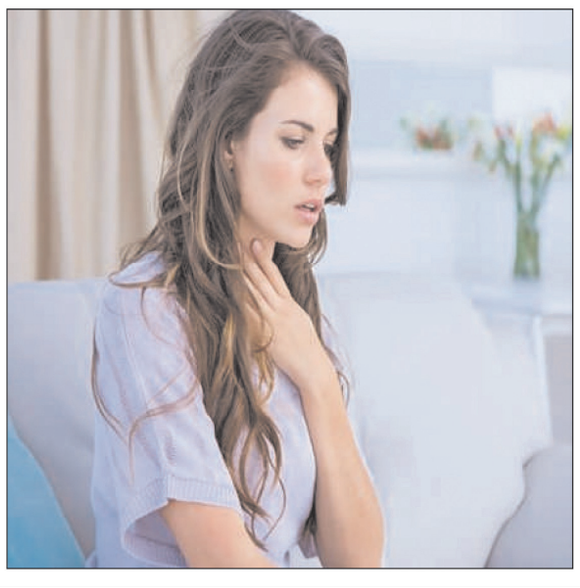

बदलते लाइफस्टाइल में सेहत से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याएं होना आम है। इन समस्याओं में हार्टबर्न, पेट संबंधी रोग, सिर दर्द, जोडों का दर्द और कफ, जुकाम और बुखार आम देखने को मिलता है। इन परेशानियों को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिस वजह से आपको कैमिकल्स युक्त दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। यह दवाइयां किसी-किसी को सूट करती है लेकिन कुछ लोगों के लिए अन्य परेशानियों का कारण बन जाती है। इससे सेहत तो खराब होती है और पैसा जाता भी दिखाई देता है। अगर आप इन रोगों का इलाज घर पर कर सकें तो कहीं ओर क्यों जाना? ऐसे में घर पर पड़ी चीजों का इस्तेमाल करें जो आपके इन छोटे-छोटे रोगों को झट से दूर कर देंगी। हम आपको एक ऐसा ही नुस्खा बताने जा रहे है जो आपके काम आएगे।

इन रोगों में काम आएगा यह नुस्खा

- वजन कम करें
- सूजन
- कमजोरी
- स्किन के लिए फायदेमंद
- कोलेस्ट्रॉल और ब्लडप्रैशर कंट्रोल
- पाचनक्रिया में सुधार
- कब्ज से राहत
- जोड़ो का दर्द
- पेट की गैस

ड्रिंक बनाने की सामग्री

- 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर
- 1 चम्मच शहद
- 1 कप Apple cider vinegar

बनाने का तरीका

ऊपर बताई सारी सामग्री को आपस मिला लें और ड्रिंक तैयार कर लें। इस ड्रिंक को रोजाना सुबह नाश्ता करने से 30 मिनट पहने पिएं। अगर आप चाहे तो जरूरत के अनुसार इस सामग्री को बढ़ा या घटा सकते है लेकिन इस नुस्खे को आजमाने से पहले अपनी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

अचारी दही भिंडी

सामग्री

500 ग्राम भिंडी, 2 बड़ा चम्मच तेल, 2 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 चौथाई छोटा चम्मच मेथी, 2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चौथाई कप दही, 1 चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर

विधि

500 ग्राम भिंडी लें। सभी के बीच में चीरा लगाकर लम्बे टुकड़े करें। 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। इसमें भिंडी तल लें। दोबारा 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। इसमें 2 छोटे चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच राई, डेढ़ छोटा चम्मच कलौंजी, एक चौथाई छोटा चम्मच मेथी दाना और चुटकीभर हींग डालकर पकाएं। अब 2 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भून लें एक चौथाई कप ताजा गाढ़ा दही लें। इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, तीन चौथाई छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। तैयार दही पैन में डालें। एक मिनट बाद इसमें तली हुई भिंडी डालकर अच्छी तरह मिला लें। दो मिनट बाद आंच से उतार लें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर भड़कीं मायावती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है. मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की और कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून के दायरे में रहकर ही लड़नी चाहिए. उनके बयान को चंद्रशेखर आजाद पर हमला माना जा रहा है. यह बयान ऐसे समय आया जब मेरठ में इस मामले के प्रदर्शन में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया और तीस से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.मायावती ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सीख है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कानून हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर लड़नी चाहिए. अगर मामला अदालत में जाए और निचली अदालत से इंसाफ न मिले तो ऊपरी अदालत का रास्ता अपनाना चाहिए क्योंकि संविधान में इसकी पूरी व्यवस्था है।

सड़कें नहीं बनीं तो जूते-चप्पल त्याग दूंगा: मोहन यादव

इंदौर। मध्य प्रदेश में विकास और सड़कों के दावों के बीच सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर से ही एक अनोखा और चर्चा का विषय बना हुआ वाकया सामने आया है. कालापीपल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपनी ही विधानसभा क्षेत्र की बदहाल और जर्जर सड़कों का मुद्दा बेहद भावुक और आक्रामक अंदाज में उठाया. विधायक ने मंच से ही कसम खा ली कि जब तक उनके क्षेत्र की सड़कों का कायाकल्प नहीं हो जाता, वे नंगे पैर ही रहेंगे.कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कहा, जब तक मेरी विधानसभा की सड़कें पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो जातीं, तब तक मैं आज से जूते-चप्पल का पूरी तरह त्याग करता हूं. इसके लिए चाहे 10 साल का लंबा समय ही क्यों न लग जाए, लेकिन जब तक सड़क नहीं बनेगी, मैं जूते-चप्पल नहीं पहनूंगा.

मेरठ जाने के रास्ते में रोके गए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद

मेरठ। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने मेरठ जाने के दौरान रास्ते में ही रूहाना टोल प्लाजा पर रोक दिया. यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर की गई. चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ के टीपी नगर में हुई बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के पीड़ित परिवार से मिलने और कलेक्ट्रेट प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रताड़ना का शिकार हुए लोगों से मिलने वहां जा रहे थे. इस दौरान टोल प्लाजा पर इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा रोके जाने और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर गाली देने की बात पर सांसद बेहद नाराज हो गए और उनकी पुलिस से सीधी झड़प हो गई.रूहाना टोल प्लाजा पर रोके जाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद गाड़ी से नीचे उतरकर इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह पर बिफर पड़े. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, चंद्रशेखर ने इंस्पेक्टर से कहा कि वे कर्मचारी हैं।

संजय राउत का दावा, गडकरी को बदनाम कर रही भाजपा

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। राउत के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की छवि को खुद भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए एक बेहद मजबूत और लोकप्रिय दावेदार हैं। संजय राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नितिन गडकरी को बदनाम करने के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता शामिल हैं, जो उन्हें जानबूझकर एक जाल में फंसाना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोका जा सके।पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने आरोप लगाया, गडकरी साहब को लेकर जनता के बीच जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें उनके ही पार्टी के लोगों का हाथ है।

चेक बाउंस केस में फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव

नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तीन महीने जेल की सजा सुनाई है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने राजपाल को दोषी मानते हुए सेशंस कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा में बदलाव किया. अदालत ने राजपाल यादव को सातों मामलों में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये की पेमेंट करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा शिकायतकर्ता को 1.04 लाख रुपये और 75 हजार रुपये, जबकि राज्य को 25 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया गया. हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये की पेमेंट करने को कहा है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राजपाल की ओर से पहले ही जमा किए जा चुके 2.25 करोड़ रुपये फाइनल पेमेंट में एडजस्ट कर दिए जाएंगे. 2010 में राजपाल ने अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ का उधार लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और राजपाल समय पर उधार चुकता नहीं कर पाए थे।

2029 तक तैयार होगी वन नेशन, वन इलेक्शन की रूपरेखा

वन नेशन, वन इलेक्शन पर लंबे समय से काम चल रहा है

नई दिल्ली। देश में वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं. इस मामले पर गठित संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि समिति ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू की जा सके. गोवा में समिति की दो दिवसीय बैठक के दौरान पीपी चौधरी ने बताया कि समिति ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की. बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है.

पीपी चौधरी ने बताया कि समिति अब तक गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गोवा समेत कई राज्यों का दौरा कर चुकी है.

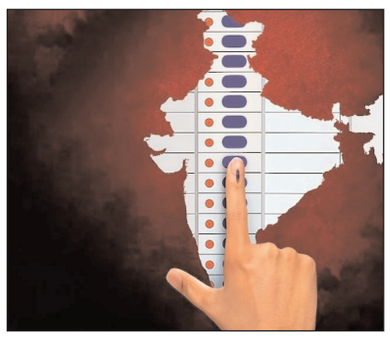

इस दौरान संवैधानिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों से राय ली गई.पीपी चौधरी ने दावा किया कि करीब 99 फीसदी नागरिक संगठनों और अन्य हितधारकों ने %वन नेशन, वन इलेक्शन% के प्रस्ताव का समर्थन किया है. समिति अब ऐसा मॉडल तैयार करने में जुटी है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बन सके. जेपीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल स्वेच्छा से तैयार हों तो 2029 से पहले भी कुछ राज्यों के चुनावी चक्र को लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ा जा सकता है.पीपी चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के समक्ष पेश आर्थिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि बार-बार अलग-अलग चुनाव होने से देश को करीब 7 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है. उनका कहना है कि एक साथ चुनाव होने से न केवल यह नुकसान रुकेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा भी होगा. चौधरी ने कहा कि लगातार चुनाव होने से प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होता है. चुनाव ड्यूटी में बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की तैनाती होने से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है, जिसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों पर पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन के चलते जल्द पिघल रहा शिवलिंग

श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर पवित्र हिम शिवलिंग के तेजी से पिघलने की खबर ने देशभर के श्रद्धालुओं और पर्यावरण विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है। तीन जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान चार जुलाई से श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू किए, लेकिन महज पांच दिनों के भीतर हिम शिवलिंग का अधिकांश हिस्सा पिघल चुका है। कई यात्रियों ने बताया कि अब केवल एक छोटा-

सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ ने इसे लगभग पूरी तरह पिघला हुआ पाया। इस स्थिति ने न केवल श्रद्धालुओं में निराशा बढ़ाई है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के गंभीर परिणामों पर भी बहस छेड़ दी है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2018 में हिम शिवलिंग लगभग 29 दिनों तक बना रहा था, जबकि 2020 में, जब कोविड-19 महामारी के कारण यात्रियों की संख्या बेहद कम थी, यह करीब 38 दिनों तक सुरक्षित रहा। वर्ष 2022 में यह लगभग 28 दिन तक रहा, जबकि इस वर्ष 2024 में यह एक सप्ताह के भीतर ही काफी हद तक पिघल गया। यह तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

भाजपा सरकार में मप्र भ्रष्टाचार का पर्याय बना : खरगे

नईदिल्ली। नयी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार के दौरान राज्य भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता के अहंकार में आकर सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की भावना को पूरी तरह कुचल दिया है।

खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी पोस्ट में दावा किया कि मध्यप्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के नाम पर 1,200 करोड़ रुपये का बड़ा चावल घोटाला सामने आया है। उन्होंने बताया कि जिस चावल का उपयोग कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए किया जाना था, उसे मुनाफे के खेल में डाइवर्ट कर दिया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकारी तंत्र और राइस मिलर्स की मिलीभगत पर सवाल उठाते हुए कहा कि करीब पांच लाख मीट्रिक टन चावल, एथेनॉल माफिया और भाजपा सरकार के संरक्षण में इस बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मिलीभगत से सीधे तौर पर जनता के हक के अनाज की चोरी की जा रही है। इसके साथ ही खरगे ने उज्जैन में हुए कथित जमीन घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन के उन्हीं क्षेत्रों में जमीनों का विस्तार किया गया जहां सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और राजमार्ग प्रस्तावित थे। इस मामले में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी सवाल खड़े हुए हैं। खरगे ने कहा कि व्यापमं से शुरू हुआ लूट और अनगिनत पेपर लीक का यह सिलसिला भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद भी आज तक नहीं रुका है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि भाजपा ने मध्यप्रदेश को भ्रष्टाचार का एक मॉडल बना दिया है, लेकिन इन सब पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह मौन साधे हुए हैं। इस आरोप पर फिलहाल मध्यप्रदेश सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान तेज

भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे चन्नी और उनके समर्थक

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जारी अंदरूनी कलह शनिवार को खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी माने जाने वाले पार्टी नेता वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के साथ उनकी बैठक हुई। बघेल भी दोपहर करीब सवा 12 बजे राणा गुरजीत के आवास पर पहुंचे थे। चन्नी और उनके करीबी वरिष्ठ नेताओं ने काफी दिनों से जारी असमंजस को समाप्त करते हुए शनिवार को बघेल से मुलाकात कर उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराने का फैसला किया था।

राणा गुरजीत सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में चन्नी के अलावा वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारत भूषण आशु, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ समेत कई प्रमुख नेता पहुंचे। इस आमंत्रण पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व उपमुख्यमंत्री ओ. पी. सोनी भी बैठक में मौजूद रहे। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था कि बघेल वहां मौजूद सभी नेताओं से संयुक्त रूप से बातचीत करेंगे या कुछ चुनिंदा नेताओं से ही मिलेंगे।

कांग्रेस आलाकमान ने बीते एक जुलाई को घोषणा की थी कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस फैसले से चन्नी नाराज बताए जा रहे थे और उन्होंने सोमवार को पंजाब पहुंचे बघेल से अब तक कोई मुलाकात नहीं की थी। शनिवार को बघेल ने

चन्नी खेमे के साथ अलग से बैठक की, जिसमें राजा वडिंग शामिल नहीं हुए।

राणा गुरजीत के आवास में प्रवेश करने से पहले चन्नी ने पत्रकारों से कहा कि वे बैठक में शामिल होकर सभी से बात करने जा रहे हैं और इसके बाद ही कोई जानकारी देंगे। जब चन्नी से पूछा गया कि क्या वे वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। समर्थकों द्वारा वडिंग का नेतृत्व स्वीकार न करने के सवाल पर चन्नी ने कहा कि पहले चर्चा कर लेने दीजिए, हमारा रुख शुरू से ही सबको पता है, बाकी तेल देखेंगे और तेल की धार देखेंगे।

बैठक में शामिल होने पहुंचे सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब पूछा गया कि क्या चन्नी खेमे ने राजा वडिंग को आमंत्रित नहीं किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वडिंग ही यह बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें बुलाया नहीं गया या वे खुद नहीं आ रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ने साफ शब्दों में कहा कि यह बैठक विशेष रूप से इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है कि वडिंग का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है या नहीं। पार्टी नेता इंदरबीर सिंह बोलारिया ने बताया कि प्रभारी भूपेश बघेल को पंजाब की जमीनी वास्तविकताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अच्छी तरह अवगत कराया जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने जीता रजत पदक

मैड्रिड। भारत की महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम को आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 के चौथे चरण में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रिथिका प्रदीप और चिकिथा तनीपार्थी की तिकड़ी फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार गई। हालांकि इस सिल्वर मेडल के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना पदक खाता खोल दिया।

मैड्रिड में खेले गए महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 14वीं रैंकिंग वाली कोलंबिया ने 232-228 से जीत दर्ज की। भारतीय टीम मुकाबले में लय हासिल नहीं कर सकी और कोलंबियाई तीरंदाजों ने शानदार निशानेबाजी के दम पर खिताब अपने नाम किया।

भारतीय टीम की सबसे अनुभवी तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम इस मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं। उन्होंने अपने आठ तीरों में केवल तीन बार ही 10 अंक हासिल किए, जिसका असर टीम के कुल स्कोर पर पड़ा। वहीं 17 वर्षीय प्रिथिका प्रदीप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह बार 10 अंक का निशाना लगाया और टीम की ओर से सबसे प्रभावशाली तीरंदाज रहीं।

कोलंबिया की अलेजांद्रा उस्कियानो ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन निशानेबाजी की। उन्होंने लगातार आठ बार 10 अंक का निशाना साधा, जो दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। पूर्व विश्व चैंपियन सारा लोपेज का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उस्कियानो ने टीम को पूरे मुकाबले में बढ़त दिलाए रखी।

भारत का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। किशोर तीरंदाज प्रिथिका प्रदीप महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और अब एक जीत उन्हें कम से कम रजत पदक दिला देगी। इसके अलावा रिकर्व वर्ग में भी भारत की उम्मीदें बरकरार हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

होम लोन में सिर्फ ईएमआई नहीं, कुल ब्याज पर करें फोकस

नई दिल्ली। घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अक्सर लोग होम लोन लेते समय सिर्फ मासिक ईएमआई पर ध्यान देते हैं। यह जल्दबाजी बाद में महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि बैंक को चुकाई जाने वाली कुल रकम आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सिर्फ ईएमआई नहीं, बल्कि कुल ब्याज और लोन की अवधि को ध्यान में रखकर ही होम लोन का फैसला लेना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक बताते हैं कि 8.5त्न ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेने पर मासिक ईएमआई भले ही करीब 43,390 रुपये लगे, लेकिन कुल चुकाई गई रकम 1.04 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जिसमें 54 लाख रुपये सिर्फ ब्याज होगा। इसका मतलब है कि आप जितनी रकम उधार लेते हैं, लगभग उतनी ही ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बने निवेशकों की पहली पसंद

नई दिल्ली। शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पर लगातार मजबूत हो रहा है। जून 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड 28,973 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश आया, जो मई के 22,907 करोड़ रुपये से 26 फीसदी अधिक है। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। इस रिकॉर्ड निवेश के साथ भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) (30 जून तक 82,22,480.04 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एएमएफआई डेटा के अनुसार मिडकैप और स्मॉलकैप फंड्स निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। मिडकैप फंड्स में सर्वाधिक 6,090 करोड़ रुपए का निवेश हुआ।

150 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हासिल करने का लक्ष्य

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि वर्ष 2030 तक 150 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तेजी से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर आधारित हो रहा है। ऐसे में भारत की नीतिगत व्यवस्था में स्थिरता और स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि इन मूल्य श्रृंखलाओं का देश में विस्तार हो सके। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियां और निर्यात आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अलग-अलग हो सकती हैं। अग्रवाल ने कहा कि चिंतन शिविर का आयोजन रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के लिए संतुलित, व्यावहारिक एवं समान अवसर वाली नीतिगत सिफारिशें तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था।

पाकिस्तान में पेट्रोल 13.18, डीजल 13.80 रु. हुआ महंगा

इस्लामाबाद। भारत में मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुई है। वहीं, पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 13.18 रुपए और हाई स्पीड डीजल का रेट 13.80 रुपए (पाकिस्तानी करेंसी) बढ़ा दिया है। यह फैसला कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से लिया गया है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 310.71 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 323.30 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे आम उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है।

भारत-यूरोप साझेदारी : व्यापार से आगे बढ़कर नए सहयोग का वक्त

श्याम सरन

ब्रसेल्स की हाल की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के वादे को पूरा करने और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में अधिक करीबी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी कायम करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

जो बात अभी भी कायम और प्रभावी है वह है इस साझेदारी की भूराजनीतिक प्रेरणा। भारत और यूरोप दोनों ही अमेरिका-चीन द्विध्रुवीय व्यवस्था की संभावना से खतरा महसूस करते हैं। यूरोप को अलग-थलग हो जाने का डर है। भारत में यह आशंका है कि वह रणनीतिक जोड़ जिसने पिछले 25 वर्षों से भारत और अमेरिका को साझेदारी में जोड़े रखा था अब कमजोर पड़ रहा है। लेकिन भारत जहां अपने हित में संप्रभु निर्णय लेता है वहीं यूरोप अब भी एक सुसंगत राजनीतिक इकाई नहीं है और यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रमुख सदस्य देश के दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। हालांकि, रूस से सुरक्षा के लगातार बने हुए खतरे और यूरोपीय सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत को लेकर आम सहमति है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जब तक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ही रूस के खिलाफ एकमात्र विश्वसनीय निवारक बना हुआ है तब तक यूरोपीय संघ की कोई भूमिका होगी या नहीं।

रूस के साथ कूटनीतिक स्तर पर नए सिरे से जुड़ाव पर भी कोई सहमति नहीं है कि यूरोप की ओर से संवाद का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और वार्ता का एजेंडा क्या होगा। ईरान युद्ध में शांति लाने के प्रयासों में यूरोप की भूमिका नगण्य रही है। चीन के मामले में भी इसी तरह तालमेल की कमी दिखाई देती है।

यह आशंका बढ़ती जा रही है कि यूरोप प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और चीन दोनों से

पिछड़ रहा है लेकिन वह कोई प्रभावी रणनीति बनाने में सक्षम नहीं है। मारियो ड्रैगी की यूरोप की प्रतिस्पर्धात्मकता पर रिपोर्ट ने इस महाद्वीप की कमजोरियों और अधिक एकीकरण तथा निवेश की आवश्यकता का एकदम स्पष्ट आकलन किया। लेकिन इस रिपोर्ट ने जिस पैमाने पर परिवर्तन की कल्पना की थी वह अब तक नहीं हुआ जबकि इसे यूरोपीय पुनरुत्थान के खाके के रूप में उद्धृत किया जाता है। यहां तक कि ड्रैगी रिपोर्ट ने भी चीन के प्रति एक विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए क्या चीन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत बैटरी तकनीकों में पकड़ बनाना बेहतर नहीं होता? क्या यूरोप के लिए यह लाभकारी नहीं होता कि वह कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों और उपकरणों से लाभ उठाए? कुछ प्रमुख यूरोपीय देश जैसे जर्मनी चीन से अधिक जुड़े हुए हैं जबकि फ्रांस उतना नहीं है। इसका अर्थ है कि यूरोप अब भी एक चीन रणनीति बनाने में असमर्थ है।

ड्रैगी रिपोर्ट में भारत का एक बार भी उल्लेख नहीं है लेकिन आशा है कि मुक्त व्यापार समझौते के निष्कर्ष के बाद यह बदल सकता है। निश्चित रूप से, ब्रसेल्स से निकला बयान यही संकेत देता है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? पहली बात, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्ता प्रक्रिया की गति धीमी न हो। मुक्त व्यापार समझौते को यथाशीघ्र अनुमोदित किया जाना चाहिए।

दूसरा, लंबित निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर पूरा किया जाना चाहिए। तीसरी बात, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) को पुन: सक्रिय कर साझेदारी का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ब्रसेल्स में हुई बातचीत से यह संदेह होता है कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) एक कठिन मुद्दा बन सकता है। आयातित वस्तुओं में कार्बन सामग्री की गणना पूरी तरह से तय नहीं हुई है।

तथाकथित मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) प्रक्रिया यूरोपीय संघ की ओर से अस्पष्ट है और यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय पक्ष द्वारा स्थापित एमआरवी को ब्रसेल्स स्वीकार करेगा या नहीं। क्या ऐसे सामान्य मानक होंगे जिन पर दोनों पक्षों के एमआरवी को समायोजित कर वास्तव में परस्पर संचालन लायक बनाया जा सके?

घोटालों को छिपाने और अपराधियों को बचाने कांग्रेस कर रही आंदोलनः शिवनारायण

- **प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय ने महादेव सट्टा एप के सौरभ चन्द्राकर और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारियों के मद्देनजर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला**

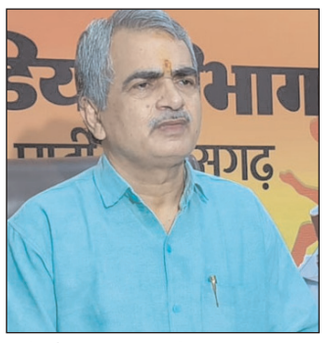

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएँ और घोटाले हुए हैं, जिसने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ के दौरान पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय ने महादेव सट्टा एप के सौरभ चन्द्राकर और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारियों के मद्देनजर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश से बाहर भेज दी गई। जब राज्य का धन दूसरे राज्यों में चला जाता है, तो स्थानीय स्तर पर मनी फ्लो (धन का प्रवाह) कम हो जाता है। यही कारण है कि पिछले लगभग ढाई साल से छत्तीसगढ़ के बाजारों में एक अजीब-सी शिथिलता देखी जा रही है। पाण्डेय ने आरोप लगाया कि जब भी इन घोटालों को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे जाते हैं, तो वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती और न ही इस पर कोई सार्थक चर्चा करना चाहती है। कांग्रेस का हमेशा यही एक घिसा-पिटा तर्क रहता है कि केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ राजनीतिक दुर्भावना या बदले की भावना से काम कर रही हैं। कांग्रेस को जाँच एजेंसियों पर सवाल उठाने के बजाय महादेव सट्टा, शराब घोटाला और राइस मिलर्स से वसूली जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अपना रुख साफ करना चाहिए। पाण्डेय ने जानना चाहा कि महादेव सट्टा एप घोटाले पर कांग्रेस का क्या कहना है? चुनाव के समय जब यह मामला उठा था, तब इसे केवल छवि खराब करने का हथकण्डा बताया गया था, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस मामले में 3,800 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। इसी प्रकार शराब घोटाला को लेकर कांग्रेस का क्या वर्जन है? राइस मिलर्स का कस्टम मिलिंग शुल्क 80 रुपये से बढ़ाकर सीधे 120 रुपए कर दिया गया और प्रति क्विंटल 20 रुपए के हिसाब से अवैध रूप से चंदा व पैसा इकट्ठा किया गया। कांग्रेस बताए कि ऐसा क्यों किया गया?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने महादेव सट्टा ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मुख्य सूत्रधार दुर्ग से ताल्लुक रखता है, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला है। क्या यह सब उनके संरक्षण और जानकारी में नहीं चल रहा था? जब कांग्रेस के तीन प्रमुख घोटालों में उनके वर्तमान कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल संलिप्त पाए जा रहे हैं, पूर्व आबकारी मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र सहित अखिल भारतीय सेवा के कई बड़े अधिकारी इन मामलों में फँसे हुए हैं; ऐसी स्थिति में कांग्रेस जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय आंदोलन का रास्ता चुन रही है। पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस में जनहित के किसी भी मुद्दे पर सड़क पर उतरने का न तो सामर्थ्य है और न ही इच्छा। पिछले ढाई साल के भाजपा शासन में कांग्रेस कभी जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर नहीं दिखी, लेकिन आज अपने चोरों, डाकुओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाने के लिए वे जिले-जिले में प्रदर्शन व आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस का साथ हमेशा से घोटालों के साथ रहा है। कांग्रेस के नेता शायद इस इंतजार में हैं कि कभी उनकी सरकार वापस आए तो वे इन घोटालों पर पर्दा डाल सकें, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है और वह इसे कभी भूलने वाली नहीं है। अब ऐसी स्थिति दोबारा आने वाली नहीं है

वन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर हरियाली रथ किया रवाना

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के प्रसार को एक जन-आंदोलन का रूप देने के लिए नारायणपुर वनमण्डल के अंतर्गत पुलिस लाइन में वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप थे। इस विशेष अवसर पर जिले के अंतर्गत शहीद हुए 118 पुलिस जवानों के नाम पर एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत शहीद वाटिका में पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक संदेश दिया गया।

शहीदों का बलिदान रहेगा चिरस्थायी- वन मंत्री

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि शहीदों की याद में लगाया गया प्रत्येक पौधा उनके सर्वोच्च बलिदान को चिरस्थायी बनाए रखने का पावन प्रतीक है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण मिल सके।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने शहीद वाटिका में स्वयं पौधा रोपित कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया। इस वाटिका में जैव विविधता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आम, अमलतास, रुद्राक्ष, आंवला, लक्ष्मणफल, अशोक, चीकू, लीची, रीठा, हल्दू, मुण्डी, गुलमोहर, साल, साजा, हर्रा, बेहड़ा, शीशम, खम्हार, बादाम, कटहल, अंजीर, युसींटा, शीशु, सेब, मालाबार नीम, बेल, मुनगा, मीठा नीम, सफेद चंदन, लाल चंदन, कनकचंपा, करंज, पीपल, सागौन, इंडियन रॉकवुड, नीम, रेन-ट्री, महुआ, एवोकाडो, रामफल, स्टारफ्रूट, कुसुम, मौसंबी, नींबू, कदंब, सिल्वर ओक, करौंदा, मोललाईट, मलबरी और सपोटा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण 118 प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है।

ट्री-एटीएम से बंटे 10 हजार पौधे

ग्रामीण अंचलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पौधों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री ने हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के ग्रामीणों को निःशुल्क 10 हजार फलदार प्रजाति के पौधों का वितरण किया गया।

सीएम सीय को बस्तर गोंचा महापर्व 2026 का निमंत्रण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में बस्तर गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गोंचा महापर्व-2026 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए महापर्व के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ को पारंपरिक रूप से दी जाने वाली सलामी तुपकी चलाकर महापर्व की सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान किया।

प्रतिनिधिमंडल ने जगदलपुर शहर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड किए जाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे शहर में विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान हुआ है तथा भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के सुचारु संचालन में आने वाली बाधाएँ भी समाप्त हो गई हैं।

360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश पाण्डे ने बताया कि समाज अपनी 619 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष 29 जून से 25 जुलाई 2026 तक बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व का आयोजन कर रहा है। भगवान श्री 1008 जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथयात्रा 16 जुलाई को श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सिरहासार भवन (जनकपुरी) में संपन्न होगी, जहाँ महाप्रभु विराजमान होंगे।

इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री किरण सिंह देव, महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री मुक्तेश पाण्डे सहित समिति के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

शिक्षा ही समृद्ध भविष्य की सबसे मजबूत नींव है : राजेश अग्रवाल

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उदयपुर में आयोजित विकासखंड स्तरीय %शाला प्रवेश उत्सव% में सहभागिता कर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाकर नवीन शैक्षणिक जीवन की शुभ शुरुआत कराई तथा अध्ययन सामग्री भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं की।

इस अवसर पर मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और संस्कारित समाज के निर्माण की आधारशिला है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहां प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखारते हुए अपने सपनों को साकार कर सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने, नियमित विद्यालय आने तथा जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया और उनकी प्रतिभा की सराहना की। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने नवीन शैक्षणिक सत्र के अवसर पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकगण को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में परिवार और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके सामूहिक प्रयासों से ही शिक्षित, जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण संभव है।

सेवा सेतु पोर्टल से ग्राम पंचायत स्तर पर मिल रही त्वरित सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासकीय सेवाएं ग्राम पंचायत स्तर पर सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में नवा रायपुर क्षेत्र के ग्राम गनौद निवासी श्री रविंद्र कुमार निर्मलकर एवं श्रीमती संध्या निर्मलकर को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से मात्र तीन दिनों में विवाह प्रमाण पत्र की सुविधा प्राप्त हुई। रविंद्र कुमार निर्मलकर एवं श्रीमती संध्या निर्मलकर को विभिन्न शासकीय एवं कानूनी कार्यों के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने 3 जुलाई 2026 को लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

शहीद भगत सिंह वार्ड को 133.08 लाख की सौगात

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और सुनियोजित अधोसंरचना विकास की दिशा में शुक्रवार को एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 में 133.08 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। टाटीबंध यदुवंशी चौक स्थित गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर, क्षेत्रीय पार्षदगण, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान टाटीबंध रायपुर में निर्मित सामुदायिक भवन तथा टाटीबंध यदुवंशी चौक स्थित अपूर्ण रंगमंच के पूर्णता कार्य का लोकार्पण किया गया। वहीं वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में नाली निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, विद्यालय में बाउंड्रीवाल, शौचालय एवं अन्य निर्माण कार्यों सहित अनेक जनोपयोगी विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन संपन्न हुआ। विकास कार्यों के शुभारंभ को लेकर स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। क्षेत्रवासियों ने वर्षों से महसूस की जा रही बुनियादी आवश्यकताओं के समाधान की दिशा में इन कार्यों को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।

आस्था पर राजनीति करना कांग्रेस का चरित्र : अमित

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो दल हमेशा प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारता रहा, जिसने सुप्रीम कोर्ट में श्रीराम को 'काल्पनिक' बताने का हलफनामा दिया, आज वही कांग्रेस 'कालनेमि' रूप धरकर रामभक्त बनने का ढोंग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर की गई पत्रकारवार्ता और अनर्गल आरोपों पर कड़ा प्रतिकार करते हुए श्री साहू ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र और राम-विरोधी मानसिकता को अच्छी तरह पहचानती है। भाजपा प्रदेश मंत्री श्री साहू ने कांग्रेस के पाखंड पर प्रहार करते हुए कहा कि रामायण में जिस प्रकार कालनेमि राक्षस ने भगवान राम के कार्य में बाधा डालने के लिए साधु का वेश धरकर हनुमान जी को गुमराह करने का प्रयास किया था, ठीक उसी तरह आज कांग्रेस के नेता रामभक्ति का चोला ओढ़कर देश की जनता को भ्रमित करने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, आज उसके मुँह से राम नाम और नैतिकता की बातें शोभा नहीं देतीं। श्री साहू ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरह से स्वतंत्र, पारदर्शी और नियमों के तहत काम करने वाली संस्था है।

बिना कार्यकारिणी के विदा हो रहे बैज : उज्जवल दीपक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल की समाप्ति पर कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कथित आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सम्भालने वाले दीपक बैज का तीन साल का कार्यकाल पूरी तरह विफल साबित हुआ है। श्री दीपक ने कहा कि गुटबाजी और अंतर्कलह के दलदल में धँसी कांग्रेस का यह हश्र होना ही था। दीपक ने तंज कसते हुए कहा कि एक तथाकथित बड़ा आदिवासी चेहरा अपने पूरे कार्यकाल में 10 उपाध्यक्ष, 23 महामंत्री और 252 सदस्यों वाली अपनी एक अदद 'पूर्ण कार्यकारिणी' तक गठित नहीं कर पाया! बिना टीम बनाए ही बैज की विदाई यह साबित करती है कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक ढाँचा पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुका है। बैज की इस बेबसी और विफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण खुद कांग्रेस का अपना पारम्परिक 'डीएनए' यानी बेलगाम गुटबाजी है। श्री दीपक ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जैसे बड़े क्षत्रपों के अपने-अपने निजी खेमों में बँटी हुई है। इन दिग्गजों के अहम् और अपने करीबियों को उपकृत करने की होड़ के बीच बैज असहाय बने रहे। इन गुटों के बीच सामंजस्य बैठाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ।

रायपुर के पं. जेएनएम मेडिकल कॉलेज में 20 एमबीबीएस सीटें बढ़ीं, कुल संख्या हुई 250

रायपुर। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (जेएनएम) मेडिकल कॉलेज, रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह कॉलेज पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ से संबद्ध है। एमएआरबी की ओर से 10 जुलाई 2026 को जारी अनुमति पत्र के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250*कर दी गई है, यानी कुल *20 नई सीटों की बढ़ोतरी हुई है। स्थापना से अब तक सीटों में वृद्धि का इतिहास वर्ष 1963 में 60 एमबीबीएस सीटों के साथ स्थापित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ने समय-समय पर अपनी प्रवेश क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। प्रारंभिक 60 सीटों से बढ़कर यह संख्या 100, वर्ष 2009 में 150, वर्ष 2019 में 180, वर्ष 2023 में 230 तथा अब एनएमसी की नवीनतम स्वीकृति के पश्चात 250 सीटों तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीटों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और वे अपने ही राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

अधिवक्ता संघ के नए पदाधिकारियों ने ली शपथ

रायपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रायपुर में अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, न्यायिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी रही। समारोह के दौरान अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश देवांगन और सचिव राकेश पूरी सहित पूरी नई कार्यकारिणी ने अपने पद और जिम्मेदारियों की शपथ ली। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और अधिवक्ताओं की भूमिका को लेकर विचार व्यक्त किए गए। वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज में न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए कहा गया कि न्याय केवल कानून की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के विश्वास और व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। अधिवक्ता

वीबी जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला पंचायत सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा

पंचायत के कार्यों में गुणवत्ता हो सर्वोच्च प्राथमिकता

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कमर कसकर अगले आठ महीनों में निर्धारित सभी लक्ष्यों को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में वीबी जीरामजी योजना एवं पंचायत विभाग के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) से जुड़े।

उप मुख्यमंत्री ने सभी जिला पंचायत सीईओ को अपने-अपने विकासखंडों का नियमित भ्रमण करने, निर्माण कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता और जवाबदेही आवश्यक है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत संतृप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्रामों में मुक्तिधाम उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मुक्तिधाम निर्माण कराने तथा अनुपयोगी एवं खराब पड़े बोरवेलों को इंजेक्शन वेल के रूप में विकसित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

वीबी जीरामजी योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने तथा सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीबी जीरामजी योजना का लाभ तेजी से प्रत्येक ग्राम तक पहुंचना चाहिए। मंत्री श्री शर्मा ने वीबी जीरामजी के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएम श्री विद्यालयों, पोटा केबिनों एवं अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण एवं शौचालय निर्माण, धरसा विकास जैसे जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए श्री शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों की समयबद्ध जियो-टैगिंग कराने तथा नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीब परिवारों के आवास निर्माण में यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है।

एनजीटी ने रायपुर स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर लगाई रोक

रायपुर। देश में बढ़ते जल संकट को गंभीरता से लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने रायपुर, मुंबई और जयपुर के तीन प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों में फिलहाल सभी खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई तक इन स्टेडियमों में एनजीटी की मंजूरी के बिना कोई भी खेल आयोजन नहीं कराया जा सकेगा। एनजीटी के अंतरिम आदेश के दायरे में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम शामिल हैं। आदेश के बाद इन तीनों स्टेडियमों में होने वाले सभी खेल आयोजनों पर फिलहाल रोक लग गई है। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि संबंधित स्टेडियमों ने भूजल के अत्यधिक उपयोग को कम करने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (स्ज्ञक्क) के शुद्ध किए गए पानी के इस्तेमाल और वर्षा जल संचयन जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया। कई बार नोटिस और निर्देश जारी होने के बावजूद संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि देश के कई हिस्से जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में बड़े खेल परिसरों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। पर्यावरणीय नियमों की लगातार अनदेखी को गंभीर मानते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगाया गया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.